नवसर्जन संस्कृति

PRGI No. GJHIN/25/A2786

नवसर्जन संस्कृति

PUBLISHED HIINDI DAILY FROM AHMEDABAD

वर्ष : 01
अंक : 217
दि. 11.05.2026,
सोमवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

'विजय युग' का आगाज: तमिलनाडु की राजनीति में ऐतिहासिक बदलाव, द्रविड़ राजनीति से इतर पहली बार नई सत्ता

चेन्नई। तमिलनाडु की राजनीति में रविवार का दिन ऐतिहासिक बन गया, जब अभिनेता से नेता बने C. Joseph Vijay ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और राज्य में एक नए राजनीतिक युग की शुरुआत हो गई। इस घटना को तमिलनाडु की छह दशक पुरानी द्रविड़ राजनीतिक परंपरा में सबसे बड़ा बदलाव माना जा रहा है, क्योंकि पहली बार राज्य की सत्ता द्रविड़ मुनेत्र कषगम (DMK) और ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम (AIADMK) से इतर किसी अन्य दल के हाथों में गई है।

राज्यपाल R. N. Ravi ने चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू इनडोर स्टेडियम में आयोजित भव्य समारोह में विजय और उनके मंत्रिमंडल के नौ सदस्यों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत वंदे मातरम और राष्ट्रगान के साथ हुई, जिसके बाद एक तमिल राष्ट्रवादी गीत ने माहौल को और भावनात्मक बना दिया।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं बल्कि तमिलनाडु की राजनीतिक पहचान में एक बड़ा मोड़ है। करीब 60 वर्षों से राज्य की राजनीति द्रविड़ विचारधारा के इर्द-गिर्द घूमती रही है, लेकिन अब Tamilaga Vettri Kazhagam (TVK) की सरकार बनने के साथ एक नई राजनीतिक धारा उभरती दिखाई दे रही है।

नए मुख्यमंत्री विजय ने अपने पहले ही संबोधन में खुद को "राजघराने से नहीं, जनता की ताकत से आगे बढ़ा नेता" बताया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार झूठे वादों पर नहीं, बल्कि ठोस काम और पारदर्शिता पर चलेगी। उन्होंने यह भी कहा कि उनके शासन में सत्ता का कोई दूसरा केंद्र नहीं होगा, जिसे राजनीतिक हलकों में द्रमुक और अन्नाद्रमुक की पारंपरिक कार्यशैली पर सीधा संकेत माना जा रहा है। शपथ लेने के तुरंत बाद विजय ने अपने पहले तीन बड़े फैसलों पर हस्ताक्षर किए,

जिनका राजनीतिक और सामाजिक दोनों स्तरों पर गहरा असर माना जा रहा है। इन फैसलों में हर घर को 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा, हर जिले में नशा विरोधी विशेष बल का गठन और महिलाओं की सुरक्षा के लिए स्पेशल टास्क फोर्स का गठन शामिल है। इन निर्णयों को नई सरकार की "फास्ट एक्शन पॉलिसी" के रूप में देखा जा रहा है।

विजय के मंत्रिमंडल में युवा और अनुभवी नेताओं का मिश्रण देखने को मिला है। द्रविड़ राजनीति के अनुभवी चेहरे केए सेंगोट्टैयन और युवा नेताओं डॉ. टीके प्रभु व एस कीर्तना सहित कुल नौ मंत्रियों ने शपथ ली। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि यह संतुलन सरकार को प्रशासनिक अनुभव और नई सोच दोनों प्रदान कर सकता है।

समारोह में कांग्रेस नेता Rahul Gandhi की मौजूदगी भी चर्चा का विषय रही। उनके मंच पर आने को राजनीतिक सहयोग और नई गठबंधन राजनीति के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। इसके अलावा वाम दलों, वीसीके और आईयूएमएल जैसे दलों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी ने भी यह संकेत दिया कि TVK को कई विपक्षी दलों का समर्थन मिला है।

विजय ने अपने संबोधन में सहयोगी दलों का धन्यवाद करते हुए कहा कि यह जीत केवल उनकी पार्टी की नहीं, बल्कि उन बच्चों की भी है जिन्होंने अपने परिवारों को मतदान के लिए प्रेरित किया। उनका यह बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ और समर्थकों के बीच उत्साह का माहौल बना।

समारोह के दौरान विजय का नाटकीय अंदाज भी चर्चा में रहा। उन्होंने भाषण के बीच रुककर अपनी कलाई घड़ी की ओर इशारा करते हुए कहा "अभी!" और इस एक शब्द ने पूरे हॉल में तालियों और नारों की गूंज पैदा कर दी। इसे उनकी आक्रामक और आत्मविश्वास से भरी राजनीति के प्रतीक के रूप में देखा जा रहा है।

विजय ने यह भी स्पष्ट किया कि उनकी सरकार में निर्णय प्रक्रिया केंद्रीकृत नहीं होगी, लेकिन जवाबदेही स्पष्ट होगी। उन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिकता सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता और विकास होगा। यह बयान राज्य की पारंपरिक द्रविड़ राजनीति के मूल मूल्यों के समानांतर एक नए राजनीतिक मॉडल की ओर संकेत करता है।

समारोह में परिवार की मौजूदगी ने भी भावनात्मक माहौल बनाया। विजय के माता-पिता एस.ए. चंद्रशेखर और शोभा चंद्रशेखर इस ऐतिहासिक क्षण पर बेहद भावुक नजर आए। उनकी मां ने कहा कि उन्हें अपने बेटे पर पूरा भरोसा है कि वह इस जिम्मेदारी को अच्छे से निभाएगा। वहीं उनकी पत्नी संगीता और बच्चे समारोह में मौजूद नहीं रहे, जिससे यह भी चर्चा का विषय बना रहा।

अभिनेत्री Trisha Krishnan की मौजूदगी ने समारोह को और भी चर्चा में ला दिया, क्योंकि उन्होंने विजय के साथ मंच साझा किया। समारोह में बड़ी संख्या में फिल्म और राजनीतिक जगत की हस्तियों की उपस्थिति रही, जिससे यह आयोजन एक राजनीतिक शपथ ग्रहण से ज्यादा एक ऐतिहासिक सार्वजनिक कार्यक्रम जैसा प्रतीत हुआ।

विजय ने अपने भाषण में कहा कि यह सिर्फ सत्ता की शुरुआत नहीं, बल्कि एक "नए तमिल युग" की शुरुआत है। उन्होंने दावा किया कि उनकी सरकार जनता के विश्वास पर खरा उतरने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध रहेगी और किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार या पक्षपात को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि TVK की यह जीत तमिलनाडु में लंबे समय से चल रही द्रविड़ पार्टियों की द्विध्रुवीय राजनीति को चुनौती दे सकती है। हालांकि यह देखना अभी बाकी है कि नई सरकार प्रशासनिक अनुभव और राजनीतिक दबावों के बीच कितना संतुलन बना पाती है।

फिलहाल तमिलनाडु की राजनीति एक नए मोड़ पर खड़ी है, जहां विजय का उदय न केवल एक नेता के रूप में, बल्कि एक "ब्रांड पॉलिटिकल आइकन" के रूप में देखा जा रहा है। आने वाले वर्षों में यह तय होगा कि यह "विजय युग" सिर्फ एक राजनीतिक लहर है या वास्तव में राज्य की राजनीति में स्थायी परिवर्तन की शुरुआत।

संकट में अडिग संकल्प: संजीव अरोड़ा को लेकर AAP नेतृत्व का समर्थन और राजनीतिक संदेश

नई दिल्ली। राजनीतिक तनाव और आरोप-प्रत्यारोप के बीच आम आदमी पार्टी (AAP) के भीतर एकजुटता और समर्थन का संदेश सामने आया है। पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक Arvind Kejriwal और पंजाब प्रभारी Manish Sisodia ने संजीव अरोड़ा के समर्थन में खुलकर बयान देते हुए उनके रुख और कार्यशैली की सराहना की है।

पार्टी नेतृत्व ने कहा कि कठिन परिस्थितियों में भी जिस तरह संजीव अरोड़ा ने अपने रुख पर अडिग रहकर निर्णय लिया, वह उनके चरित्र और राजनीतिक ईमानदारी को दर्शाता है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि किसी भी व्यक्ति का असली चरित्र तब सामने आता है जब वह संकट का सामना करता है, और ऐसे समय में अरोड़ा ने अपने मूल्यों से समझौता नहीं किया। पार्टी की ओर से यह भी आरोप लगाया गया कि संजीव अरोड़ा को एक फर्जी मामले में फंसाकर गिरफ्तार किया गया है, जो केवल एक व्यक्ति पर कार्रवाई नहीं बल्कि जनता के विश्वास और विकास की प्रक्रिया पर हमला है। हालांकि इन आरोपों पर संबंधित जांच एजेंसियों की ओर से विस्तृत प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन राजनीतिक बहस तेज हो गई है।

पंजाब में सत्ता संभाल रही सरकार के भीतर भी यह मामला चर्चा में है, क्योंकि अरोड़ा को पार्टी

का एक सक्रिय और कामकाजी चेहरा माना जाता रहा है। उनके कार्यों को लेकर पार्टी का कहना है कि उन्होंने शहरों के बुनियादी ढांचे को सुधारने और आधुनिक बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

Manish Sisodia ने संजीव अरोड़ा को "विजनरी और मेहनती नेता" बताते हुए कहा कि उन्होंने शहरी विकास के कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में काम किया है। इनमें स्ट्रीट लाइट व्यवस्था को बेहतर बनाना, बिजली के तारों के अव्यवस्थित जाल को सुधारना और आधुनिक अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर की दिशा में प्रयास शामिल हैं।

पार्टी नेताओं का कहना है कि अरोड़ा ने न केवल शहरों के विकास पर ध्यान दिया, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने के प्रयास किए। विशेष रूप से खेतों और गांवों में फैले खुले बिजली तारों को अंडरग्राउंड करने जैसी योजनाओं में उनकी सक्रिय भूमिका रही है। इसे सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक माना जा रहा है।

पार्टी का यह भी दावा है कि इन परियोजनाओं का उद्देश्य केवल तकनीकी सुधार नहीं, बल्कि आम जनता के जीवन को सुरक्षित और सुविधाजनक बनाना है। अरोड़ा को इसी सोच का प्रतिनिधि नेता बताया जा रहा है, जो जमीनी स्तर पर बदलाव लाने में विश्वास रखते हैं।

राजनीतिक हलकों में इस पूरे घटनाक्रम को केवल एक कानूनी या प्रशासनिक मामला नहीं, बल्कि एक व्यापक राजनीतिक संदेश के रूप में देखा जा रहा है। AAP नेतृत्व लगातार यह संकेत देने की कोशिश कर रहा है कि पार्टी अपने नेताओं के साथ खड़ी है और किसी भी तरह के दबाव में झुकने वाली नहीं है।

केजरीवाल ने अपने बयान में यह भी कहा कि अरोड़ा ने किसी राजनीतिक दबाव या अवसर के बजाय कठिन रास्ता चुना, और इसी वजह से उनकी प्रशंसा की जानी चाहिए। उनके अनुसार, "भाजपा में जाने की बजाय जेल जाना पसंद करना" एक साहसिक निर्णय है, जिसे पार्टी एक नैतिक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत कर रही है।

वहीं दूसरी ओर राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस तरह के बयान केवल व्यक्तिगत समर्थन तक सीमित नहीं रहते, बल्कि यह विपक्षी दलों के खिलाफ एक राजनीतिक नैरेटिव बनाने का प्रयास भी होते हैं। ऐसे मामलों में अक्सर न्यायिक प्रक्रिया और राजनीतिक बयानबाजी एक साथ चलती हैं, जिससे स्थिति और जटिल हो जाती है।

पंजाब की राजनीति में पहले से ही कई मुद्दों को लेकर टकराव की स्थिति बनी हुई है, ऐसे में यह मामला भी राजनीतिक बहस को और तेज कर सकता है। पार्टी समर्थकों का मानना है कि अरोड़ा के खिलाफ कार्रवाई अनुचित है, जबकि आलोचकों का कहना है कि किसी भी मामले की निष्पक्ष जांच आवश्यक है।

फिलहाल पार्टी नेतृत्व अपने रुख पर कायम है और संजीव अरोड़ा को एक ईमानदार, मेहनती और विकासोन्मुखी नेता के रूप में पेश कर रहा है। यह मामला आने वाले समय में राजनीतिक और कानूनी दोनों स्तरों पर और अधिक चर्चा का विषय बन सकता है।

कुल मिलाकर, यह प्रकरण केवल एक व्यक्ति से जुड़ा मामला नहीं रह गया है, बल्कि यह राजनीतिक विश्वास, नेतृत्व की छवि और प्रशासनिक प्रक्रियाओं पर उठते सवालों से भी जुड़ गया है।

महाराष्ट्र सदन में बदलेगी वाहन व्यवस्था, मुख्यमंत्री के लिए नई बुलेटप्रूफ कार की मंजूरी; सुरक्षा और आधुनिकीकरण पर जोर

मुंबई/नई दिल्ली। महाराष्ट्र सरकार ने प्रशासनिक और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा निर्णय लिया है। सरकार ने नई दिल्ली स्थित Maharashtra Sadan में उपयोग की जा रही पुरानी सरकारी गाड़ियों को बदलने और नई वाहनों की खरीद को मंजूरी दे दी है। इस फैसले के तहत पुराने वाहनों की नीलामी की जाएगी और उनकी जगह आधुनिक सुरक्षा मानकों से लैस नई गाड़ियां शामिल की जाएंगी।

सरकारी आदेश के अनुसार महाराष्ट्र सदन में तैनात तीन पुराने वाहनों को चरणबद्ध तरीके से नीलाम किया जाएगा। इन वाहनों में एक बुलेटप्रूफ वाहन और दो सामान्य उपयोग की गाड़ियां शामिल हैं। इनके स्थान पर नई गाड़ियों की खरीद राज्य सरकार की निर्धारित वाहन नीति और वित्त विभाग के नियमों के तहत की जाएगी।

इस निर्णय का सबसे अहम पहलू मुख्यमंत्री के लिए नई बुलेटप्रूफ कार की खरीद है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह वाहन सुरक्षा आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए खरीदा जाएगा और इसका खर्च राज्य सरकार के संबंधित बजट मद से वहन किया जाएगा। यह कदम मुख्यमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने की दिशा में उठाया गया है।

सूत्रों के अनुसार यह निर्णय हाल ही में हुई उच्च स्तरीय बैठक में सुरक्षा एजेंसियों की सिफारिशों के आधार पर लिया गया है। पुरानी गाड़ियों की तकनीकी स्थिति और सुरक्षा मानकों को देखते हुए उन्हें बदलना आवश्यक माना गया। इसके बाद सरकार ने यह तय किया कि आधुनिक तकनीक और बेहतर सुरक्षा सुविधाओं से लैस वाहन खरीदे जाएं।

सरकारी अधिकारियों का कहना है कि यह केवल वाहन बदलने का निर्णय नहीं है, बल्कि यह प्रशासनिक सुरक्षा ढांचे के आधुनिकीकरण का हिस्सा है। मुख्यमंत्री और अन्य वीआईपी व्यक्तियों की सुरक्षा में बुलेटप्रूफ वाहनों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, खासकर बड़े सार्वजनिक कार्यक्रमों और यात्रा के दौरान।

नई गाड़ियों की खरीद प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी तरीके से की जाएगी। इसके लिए टेंडर जारी किए जाएंगे और चयन प्रक्रिया राज्य सरकार की वित्तीय नियम पुस्तिका और सार्वजनिक खरीद नीति के अनुसार होगी। सरकार का दावा है कि पूरी प्रक्रिया में वित्तीय अनुशासन और पारदर्शिता को प्राथमिकता दी जाएगी।

पुराने वाहनों की नीलामी भी नियमानुसार सरकारी परिवहन सेवा के माध्यम से की जाएगी। इससे न केवल पुराने वाहनों का उचित निस्तारण होगा, बल्कि सरकारी संसाधनों के बेहतर उपयोग की दिशा में भी यह कदम महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

विशेषज्ञों का मानना है कि सरकारी वाहनों के नियमित अपग्रेडेशन से प्रशासनिक कार्यक्षमता और सुरक्षा दोनों में सुधार होता है। खासकर बुलेटप्रूफ वाहनों की तकनीक समय के साथ पुरानी हो जाती है, जिससे सुरक्षा मानकों पर असर पड़ सकता है। ऐसे में समय-समय पर इनका प्रतिस्थापन आवश्यक माना जाता है।

इस निर्णय को राज्य सरकार की उस व्यापक नीति से भी जोड़कर देखा जा रहा है, जिसमें सरकारी तंत्र को आधुनिक और तकनीकी रूप से सक्षम बनाने पर जोर दिया जा रहा है। पिछले कुछ वर्षों में कई राज्यों ने भी इसी तरह अपने वीआईपी सुरक्षा बेड़े को अपग्रेड किया है।

राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में इस फैसले को सामान्य प्रक्रिया के रूप में देखा जा रहा है, हालांकि कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे निर्णयों में खर्च और प्राथमिकताओं का संतुलन भी महत्वपूर्ण होता है। लेकिन सरकार का पक्ष है कि सुरक्षा से समझौता किसी भी स्थिति में नहीं किया जा सकता।

मुख्यमंत्री और राज्यपाल जैसी संवैधानिक पदों की सुरक्षा को देखते हुए बुलेटप्रूफ वाहनों का उपयोग मानक प्रोटोकॉल का हिस्सा होता है। इसी प्रोटोकॉल के तहत नई बुलेटप्रूफ कार की खरीद को मंजूरी दी गई है, जिससे यात्रा और सार्वजनिक कार्यक्रमों के दौरान सुरक्षा और मजबूत हो सके।

कुल मिलाकर, यह निर्णय महाराष्ट्र सरकार की उस नीति का हिस्सा है, जिसमें प्रशासनिक ढांचे को आधुनिक बनाने, सुरक्षा मानकों को मजबूत करने और सरकारी संसाधनों के प्रभावी उपयोग पर जोर दिया जा रहा है। आने वाले समय में टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद नई गाड़ियों का बेड़ा महाराष्ट्र सदन में शामिल कर दिया जाएगा।

'आर्थिक आत्मनिर्भरता' पर जोर: PM मोदी की जनता से अपील एक साल तक सोना खरीदने से बचें और ईंधन की बचत करें

सिकंदराबाद। वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं और अंतरराष्ट्रीय संघर्षों के बीच प्रधानमंत्री Narendra Modi ने देशवासियों से एक अहम अपील की है। तेलंगाना के सिकंदराबाद में आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए नागरिकों को आर्थिक अनुशासन अपनाना चाहिए और देश की विदेशी मुद्रा बचाने में सहयोग करना चाहिए।

प्रधानमंत्री ने लोगों से आग्रह किया कि वे अगले एक वर्ष तक सोना खरीदने से परहेज करें और पेट्रोल-डीजल की खपत को कम करें। उन्होंने कहा कि आज दुनिया जिस दौर से गुजर रही है, उसमें हर देश अपनी आर्थिक स्थिरता और ऊर्जा संसाधनों को सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहा है, ऐसे में भारत को भी सामूहिक जिम्मेदारी निभानी होगी। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में यह भी कहा कि पश्चिम एशिया और यूक्रेन जैसे क्षेत्रों में जारी संघर्षों का असर केवल उन देशों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका प्रभाव वैश्विक सप्लाई चेन, ऊर्जा बाजार और अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर भी पड़ रहा है। इसी वजह से भारत जैसे बड़े आयात-निर्भर देश को अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत है।

उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि शादियों और पारिवारिक आयोजनों में सोने की खरीद एक परंपरा रही है, लेकिन मौजूदा समय में यह आवश्यक है कि लोग "अनावश्यक खर्चों" को टालें। उनका कहना था कि यदि देश के नागरिक कुछ समय के लिए सोने की खरीद कम करते हैं तो इससे विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव घटेगा और आर्थिक स्थिरता को मजबूती मिलेगी।

ऊर्जा खपत को लेकर प्रधानमंत्री ने विशेष रूप से पेट्रोल और डीजल की बचत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि वैश्विक बाजार में ईंधन की कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव देखा जा रहा है, जिसका सीधा असर आम जनता और देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। ऐसे में ईंधन का समझदारी से उपयोग करना हर नागरिक की जिम्मेदारी है।

प्रधानमंत्री ने यह भी याद दिलाया कि कोविड-19 महामारी के दौरान देश ने कैसे डिजिटल माध्यमों को अपनाकर कार्य संस्कृति में बड़ा बदलाव किया था। उन्होंने सुझाव दिया कि आवश्यकता पड़ने पर वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन मीटिंग और डिजिटल संपर्क जैसे विकल्पों को फिर से प्राथमिकता दी जा सकती है, जिससे ईंधन की खपत कम हो और प्रदूषण पर भी नियंत्रण पाया जा सके।

सभा के दौरान उन्होंने कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का भी उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार किसानों को सस्ती दरों पर खाद उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने दावा किया कि जहां वैश्विक बाजार में एक बोरी खाद की कीमत हजारों रुपये तक पहुंच जाती है, वहीं भारत में किसानों को यह काफी कम कीमत पर उपलब्ध कराई जा रही है।

इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने खाद्य तेल की खपत कम करने और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की भी अपील की। उनका कहना था कि स्वस्थ जीवनशैली और टिकाऊ कृषि मॉडल दोनों ही देश के भविष्य के लिए जरूरी हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार लंबे समय से ऐसे उपायों पर काम कर रही है जिनसे देश आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से बढ़ सके।

प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में वैश्विक राजनीति का भी जिक्र किया और कहा कि कई अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम भारत की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हैं। ऐसे में जनता का सहयोग बेहद जरूरी है ताकि देश आर्थिक रूप से मजबूत बना रह सके।

सभा में उन्होंने राजनीतिक मुद्दों पर भी टिप्पणी की और विपक्षी दलों पर परोक्ष रूप से निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कुछ राजनीतिक ताकतें परिवारवाद और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती रही हैं, लेकिन देश की जनता अब बदलाव और विकास की राजनीति को प्राथमिकता दे रही है।

प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि हाल के समय में देश में एक नई राजनीतिक और आर्थिक सोच विकसित हो रही है, जिसमें पारदर्शिता, विकास और आत्मनिर्भरता को केंद्र में रखा गया है। उन्होंने जनता से अपील की कि वे इस परिवर्तन यात्रा का हिस्सा बनें और देश के विकास में योगदान दें।

विशेषज्ञों का मानना है कि प्रधानमंत्री की यह अपील केवल आर्थिक सलाह नहीं है, बल्कि यह व्यापक स्तर पर उपभोक्ता व्यवहार को प्रभावित करने की एक रणनीति भी है। सोने की खपत भारत में न केवल सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह आयात बिल को भी प्रभावित करती है। इसी तरह पेट्रोल-डीजल की खपत सीधे तौर पर विदेशी मुद्रा भंडार और पर्यावरण दोनों से जुड़ी हुई है।

हालांकि इस तरह की अपील पर आम जनता की प्रतिक्रिया मिश्रित हो सकती है, क्योंकि सोना भारतीय समाज में केवल निवेश नहीं बल्कि परंपरा और सामाजिक रीति-रिवाजों का हिस्सा भी है। वहीं ईंधन की खपत कम करना भी शहरी जीवनशैली में व्यवहारिक चुनौती पेश करता है।

इसके बावजूद सरकार का मानना है कि यदि नागरिक छोटी-छोटी बचत और समझदारी भरे फैसले अपनाते हैं, तो इसका बड़ा प्रभाव राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। प्रधानमंत्री का संदेश इसी सामूहिक प्रयास की ओर संकेत करता है, जहां सरकार और जनता मिलकर आर्थिक स्थिरता को मजबूत कर सकते हैं।

संपादकीय

बंगाल की राजनीति में अब मुद्दों नहीं, स्वादों का मुकाबला

भारतीय राजनीति अपने रंग, रूप और अंदाज बदलने में जितनी तेज है, उतनी शायद दुनिया की कोई दूसरी लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं होगी। यहां चुनाव केवल नीतियों, घोषणापत्रों और विकास योजनाओं पर नहीं लड़े जाते, बल्कि भावनाओं, प्रतीकों, खान-पान, पहनावे और सांस्कृतिक संकेतों पर भी लड़े जाते हैं। कभी नेता मंदिरों के दर्शन से चर्चा में आते हैं, कभी चाय की दुकान से और कभी सड़क किनारे किसी स्थानीय व्यंजन का स्वाद लेकर जनता से जुड़ने की कोशिश करते हैं। पश्चिम बंगाल के हालिया चुनावों ने तो राजनीति को जैसे एक नया स्वाद ही दे दिया। यहां चर्चा विकास, उद्योग, रोजगार और शिक्षा से ज्यादा झालमुड़ी, मछली और फुटबॉल की होने लगी। ऐसा लगने लगा कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी बहस अब राजनीतिक विचारधाराओं के बीच नहीं, बल्कि स्वादों और प्रतीकों के बीच चल रही है। बंगाल में भाजपा की जीत के बाद व्यंग्य और राजनीतिक चर्चाओं में यह बात तेजी से फैलने लगी कि इस चुनाव में असली कमाल दस रुपये की झालमुड़ी ने कर दिया। विरोधी दल चाहे भाजपा पर धनबल और संसाधनों के दम पर चुनाव जीतने का आरोप लगाते रहें, लेकिन जनता और सोशल मीडिया की राजनीति अलग ही दिशा में चलती दिखाई दी। वहां यह कहा जाने लगा कि बड़े-बड़े भाषण, रैलियां और विज्ञापन अपनी जगह, लेकिन जनता के मन पर असर तो उस साधारण सी झालमुड़ी ने डाला जिसे प्रधानमंत्री ने बड़े सहज अंदाज में खाया था। बंगाल की गलियों में मिलने वाली यह मामूली चीज अचानक राजनीतिक प्रतीक बन गई। जिस तरह उत्तर भारत में बुलडोजर एक राजनीतिक संदेश बन गया था, वैसे ही बंगाल में झालमुड़ी आम आदमी से जुड़ाव और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक बनती दिखाई दी। राजनीति में प्रतीकों का महत्व हमेशा से रहा है। महात्मा गांधी का चरखा, लालू प्रसाद की लालटेन, मायावती का हाथी, समाजवादी पार्टी की साइकिल और भाजपा का कमल — सबने समय-समय पर जनता के बीच गहरी छाप छोड़ी है। लेकिन बंगाल चुनाव ने यह दिखाया कि अब साधारण खान-पान भी राजनीति का हिस्सा बन सकता है। जब प्रधानमंत्री ने झालमुड़ी खाई, तो यह केवल एक नाश्ता खाने की घटना नहीं रही। यह एक संदेश था कि भाजपा बंगाल की संस्कृति, स्वाद और जीवनशैली से खुद को जोड़ना चाहती है। राजनीति में ऐसे छोटे दृश्य कई बार बड़े भाषणों से ज्यादा असर डालते हैं। ममता बनर्जी लंबे समय तक बंगाल की राजनीति की सबसे ताकतवर नेता मानी जाती रही हैं। उनकी छवि एक संघर्षशील और आक्रामक नेता की रही है। उन्हें "बंगाल की शेरनी" कहा जाता रहा। लेकिन चुनावी नतीजों के बाद राजनीतिक व्यंग्य में यह कहा जाने लगा कि अब उनकी दहाड़ कमजोर पड़ गई है। राजनीति में हार और जीत दोनों अस्थायी होती हैं, लेकिन व्यंग्यकार इन्हीं क्षणों को पकड़कर जनता के बीच नए प्रतीक गढ़ देते हैं। यही कारण है कि अब बंगाल की राजनीति में झालमुड़ी और शेरनी दोनों साथ-साथ चर्चा में आने लगे हैं। इसी दौरान मछली ने भी चुनावी माहौल में अपनी अलग जगह बना ली। बंगाल और मछली का रिश्ता केवल भोजन का नहीं, बल्कि संस्कृति और पहचान का भी है। बंगाली समाज में मछली केवल खाने की चीज नहीं, बल्कि सामाजिक जीवन का हिस्सा मानी जाती है। ऐसे में जब नेताओं ने मछली को लेकर बयान देने शुरू किए, तो वह भी राजनीति का विषय बन गया। अनुराग ठाकुर के मछली खाने की चर्चा हो या रवि किशन का यह कहना कि बंगालियों को चार गुना ज्यादा मछली खिलाई जाएगी, हर बयान सुर्खियों में आ गया। हालांकि जनता अब राजनीतिक वादों को लेकर पहले जैसी भावुक नहीं रही। इसलिए कई लोगों ने मजाक में यह कहना शुरू कर दिया कि कहीं यह वादा भी उन चुनावी वादों जैसा न निकले जिनका जिक्र चुनाव खत्म होते ही गायब हो जाता है। सबसे ज्यादा चर्चा उस बयान की हुई जिसमें हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा कि वह ममता बनर्जी से एक किलो ज्यादा मछली खा सकते हैं। भारतीय राजनीति के इतिहास में शायद यह पहला दौर होगा जब नेताओं के बीच मुकाबला इस बात पर दिखाई देने लगा कि कौन ज्यादा खा सकता है। कभी राजनीति में सादगी की होड़ हुआ करती थी। नेता यह दिखाने की कोशिश करते थे कि वे कितना साधारण जीवन जीते हैं। फिर समय बदला और घोटालों की तुलना होने लगी। अब राजनीति मनोरंजन, तंज और सोशल मीडिया की भाषा में ढलती जा रही है। ऐसे में मछली खाने की चुनौती भी राजनीतिक चर्चा का हिस्सा बन जाती है।

प्रोजेक्ट और पेटेंट बन गए करिअर की नींव

> सही मायने जो छात्र अपने ज्ञान को नवाचार और व्यावहारिक उपलब्धियों के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं, वे न केवल नियोक्ताओं को बल्कि समाज को भी यह बताते हैं कि भारत का युवा केवल डिग्रीधारी नहीं, बल्कि समाधानकर्ता और निर्माता है।

आज के प्रतिस्पर्धी शैक्षणिक और व्यावसायिक परिवेश में केवल डिग्री प्राप्त करना किसी छात्र की योग्यता का पर्याप्त प्रमाण नहीं माना जाता। नियोक्ता अब ऐसे युवाओं की तलाश में हैं जो न केवल पाठ्यपुस्तकों के ज्ञान से परिचित हों, बल्कि वास्तविक जीवन की जटिल समस्याओं को सुलझाने की दृष्टि व क्षमता भी रखते हों। हाल ही में बी.टेक के कुछ प्रतिभाशाली छात्रों की एक प्रेरणादायक कहानी सामने आई, जिन्होंने अपनी पढ़ाई के साथ-साथ उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल कीं। एक अत्याधुनिक कृषि-तकनीक परियोजना और एक पेटेंटेड जूते का डिज़ाइन और इन्हीं उपलब्धियों ने उनके करिअर का मार्ग प्रशस्त किया। पहली उपलब्धि थी एक अनूठी कृषि-तकनीक परियोजना, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी) को मशरूम की व्यावसायिक खेती के साथ जोड़ा गया। मशरूम की खेती एक अत्यंत संवेदनशील प्रक्रिया है, जिसमें तापमान, आर्द्रता, प्रकाश व वायु संचरण का सटीक नियंत्रण अनिवार्य होता है। यह कार्य पूरी तरह मानवीय श्रम पर निर्भर था, जिससे न केवल उत्पादन लागत बढ़ती थी, बल्कि मानवीय चूक से फसल खराब होने का जोखिम भी रहता था।

इन छात्रों ने आईओटी सेंसर्स, स्वचालित एक्चुएटर्स और एआई आधारित डेटा विश्लेषण को मिलाकर एक ऐसा स्मार्ट सिस्टम विकसित किया, जो मशरूम फार्म की पर्यावरणीय परिस्थितियों की रियल-टाइम निगरानी करता है और आवश्यकतानुसार स्वतः समायोजन करता है। इस प्रणाली की उल्लेखनीय उपलब्धि यह रही कि इसने मशरूम उत्पादन में मैन्युअल हस्तक्षेप को पचास प्रतिशत तक कम किया। यानी आधी मेहनत, आधी लागत और दोगुनी दक्षता। परियोजना ने न केवल स्थानीय किसानों की उत्पादकता में सुधार का मार्ग दिखाया, बल्कि बताया कि आधुनिक तकनीक कृषि क्षेत्र में किस प्रकार क्रांतिकारी बदलाव ला सकती है।

इस प्रोजेक्ट के दौरान छात्रों ने गहन शोध किया, विशेषज्ञों से मार्गदर्शन पाया और तकनीकी बाधाओं को पार कर एक कार्यशील प्रोटोटाइप तैयार किया। परियोजना केवल एक शैक्षणिक अभ्यास नहीं थी—वरन वास्तविक समस्या का वास्तविक समाधान था, जो उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप था व किसानी जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डालने में सक्षम था।

इसके समानांतर, इन छात्रों ने एक बिल्कुल भिन्न क्षेत्र में भी अपनी रचनात्मकता का परिचय दिया। उन्होंने एक विशेष जूते के तलवे का डिज़ाइन तैयार किया, जो एड़ी की समस्याओं जैसे प्लांटर फेसाइटिस, हील स्पर और दीर्घकालिक एड़ी दर्द से पीड़ित लोगों को अधिकतम आराम और राहत प्रदान करने के लिए तैयार किया गया है। यह महज एक फुटवियर उत्पाद नहीं, बल्कि स्वास्थ्य-केंद्रित इंजीनियरिंग समाधान है। इस डिज़ाइन में बायोमेकेनिकल सिद्धांतों का उपयोग करते हुए एड़ी पर पड़ने वाले दबाव को समान रूप से वितरित किया गया है, जिससे चलने-फिरने के दौरान दर्द में खासी कमी आती है। इस डिज़ाइन की मौलिकता और व्यावसायिक संभावनाओं को देखते हुए छात्रों ने इसके लिए पेटेंट आवेदन दाखिल किया। पेटेंट प्राप्त करना किसी भी इंजीनियरिंग छात्र के लिए एक असाधारण उपलब्धि है, जो आधिकारिक प्रमाण है कि उनका विचार मौलिक, उपयोगी और संरक्षण के योग्य है। इस पेटेंट ने न केवल उनके बौद्धिक योगदान को मान्यता दी, बल्कि उनके रिज़्यूमे को एक ऐसी विशिष्टता प्रदान की, जो किसी भी परीक्षा में अर्जित अंकों से अधिक प्रभावशाली थी।

जब ये छात्र नौकरी के लिए साक्षात्कार देने पहुंचे, तो उनके रिज़्यूमे ने साक्षात्कारकर्ताओं का ध्यान आकर्षित किया। सामान्यतः फ्रेशर्स से शैक्षणिक ज्ञान की ही अपेक्षा की जाती है, परंतु इन छात्रों के पास इससे कहीं अधिक था— एक सिद्ध परियोजना, जिसने कृषि क्षेत्र में पचास फीसदी श्रम कम किया, और एक पेटेंटेड आविष्कार जो लाखों लोगों के दैनिक जीवन को प्रभावित करने की क्षमता रखता था। साक्षात्कार के दौरान उन्होंने अपनी परियोजना की तकनीकी कार्यप्रणाली, विकास के दौरान आई चुनौतियों व समाधान के बारे में विस्तार से बताया।

कंपनियों के प्रतिनिधियों ने महसूस किया कि ये युवा न केवल सैद्धांतिक रूप से सक्षम हैं, बल्कि व्यावहारिक समस्याओं की पहचान कर उनका समाधान ढूंढ़ने की दुर्लभ प्रतिभा भी रखते हैं। उनकी इस बहुआयामी क्षमता— जो एआई और आईओटी जैसी अत्याधुनिक तकनीकों से लेकर उत्पाद डिज़ाइन और बौद्धिक संपदा तक फैली हुई थी, ने उन्हें हजारों अन्य उम्मीदवारों की भीड़ में स्पष्ट रूप से अलग और विशिष्ट बना दिया। परिणामस्वरूप, उन्हें प्रतिष्ठित कंपनियों से आकर्षक जॉब ऑफर प्राप्त हुए और उन्होंने एक उज्ज्वल करिअर की नींव रखी।

निस्संदेह, यह प्रेरक उदाहरण हर उस छात्र हेतु महत्वपूर्ण संदेश है जो अपने करिअर को लेकर गंभीर हैं। खासकर सीएसई, आईटी, ईसीई, मैकेनिकल और सिविल इंजीनियरिंग के विद्यार्थी समझें कि परीक्षाओं में अच्छे अंक लाना तो आवश्यक है, किंतु यही सब कुछ नहीं है। नौकरी बाज़ार में वही छात्र आगे निकलते हैं जो अपनी पढ़ाई के साथ-साथ नवाचार, शोध और व्यावहारिक कार्यों में भी हाथ आज़माते हैं। एक सशक्त प्रोजेक्ट और एक पेटेंट केवल कागज़ की उपलब्धियां नहीं हैं — ये छात्र की चिंतन, समस्या-समाधान की क्षमता और उद्यमशीलता की भावना के जीवंत प्रमाण हैं।

प्रेरणा

संवेदनाओं, संघर्षों और समय चेतना का सशक्त काव्य संसार

हिंदी साहित्य की समृद्ध परंपरा में कविता हमेशा मनुष्य के भीतर चल रही हलचलों की सबसे प्रामाणिक अभिव्यक्ति रही है। कविता केवल भावनाओं का विस्तार नहीं होती, बल्कि वह समय, समाज और मनुष्य के अंतर्मन के बीच चल रहे संवाद का जीवंत दस्तावेज भी होती है। हर दौर में कवियों ने अपने-अपने अनुभवों, संघर्षों और संवेदनाओं को शब्द देकर समाज के सामने रखा है। किसी ने व्यवस्था की विसंगतियों पर प्रहार किया, किसी ने टूटते रिश्तों की पीड़ा को स्वर दिया, तो किसी ने मनुष्य के भीतर बसे अकेलेपन, उम्मीद और स्मृतियों को अपनी रचनाओं का केंद्र बनाया। समकालीन हिंदी कविता में दिलीप कुमार पाण्डेय का काव्य संग्रह 'मैं समय हूं' इसी परंपरा का एक महत्वपूर्ण और संवेदनशील हस्ताक्षर बनकर सामने आता है।

यह संग्रह केवल कविताओं का संकलन नहीं है, बल्कि मनुष्य के भीतर घटित होने वाले उन अनुभवों की यात्रा है, जिन्हें अक्सर शब्द नहीं मिल पाते। संग्रह में शामिल अड़सठ कविताएं जीवन के विभिन्न आयामों को बेहद आत्मीयता और गहराई के साथ प्रस्तुत करती हैं। इन कविताओं को पढ़ते हुए यह महसूस होता है कि कवि ने जीवन को केवल बाहर से नहीं देखा, बल्कि उसे भीतर तक जिया और महसूस किया है। यही कारण है कि उनकी कविताओं में कृत्रिमता या बनावटीपन नहीं दिखाई देता, बल्कि जीवन की सच्चाइयों की सीधी और ईमानदार अभिव्यक्ति दिखाई देती है। दिलीप कुमार पाण्डेय की कविताओं की सबसे बड़ी विशेषता उनकी संवेदनात्मक गहराई है। वे अपनी रचनाओं में किसी तरह की अतिनाटकीयता या अनावश्यक भावुकता का सहारा नहीं लेते। आज के समय में जहां बहुत-सी रचनाएं केवल तात्कालिक प्रतिक्रिया बनकर रह जाती हैं, वहीं उनकी कविताएं गंभीर चिंतन और आत्ममंथन का परिणाम प्रतीत होती हैं। वे समाज में मौजूद विसंगतियों को केवल उजागर नहीं करते, बल्कि उनके पीछे छिपी मानवीय पीड़ा और मनोवैज्ञानिक स्थितियों को भी समझने का प्रयास करते हैं। यही कारण है कि उनकी कविताएं केवल पढ़ी नहीं जातीं, बल्कि महसूस की जाती हैं। 'मैं समय हूं' शीर्षक अपने आप में गहरी दार्शनिक चेतना से जुड़ा हुआ है। समय मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। वह न रुकता है, न पीछे लौटता है और न ही किसी के लिए अपने नियम बदलता है। संग्रह की शीर्षक कविता "समय रुकता नहीं" में कवि लिखते हैं — समय सच है/ अटल भी है/ इधर-उधर मुड़कर नहीं देखता/ अपनी गति से/ निरंतर चलता रहता है।" इन पंक्तियों में जीवन का गहरा दर्शन छिपा हुआ है। कवि यहां केवल समय की निरंतरता की बात नहीं कर रहे, बल्कि मनुष्य की सीमाओं और उसके भ्रमों को भी सामने ला रहे हैं। मनुष्य अक्सर अपने जीवन की योजनाओं, इच्छाओं और अपेक्षाओं में उलझा रहता है, जबकि समय बिना रुके आगे बढ़ता रहता है। यही द्वंद्व जीवन का सबसे बड़ा यथार्थ बन जाता है। संग्रह की कविताओं में मनुष्य के भीतर की टूटन और चुप्पियों का अत्यंत मार्मिक चित्रण मिलता है। आधुनिक जीवन में रिश्ते लगातार जटिल होते जा रहे हैं। संवाद कम हो रहे हैं और अकेलापन बढ़ता जा रहा है। दिलीप कुमार पाण्डेय इन स्थितियों को बहुत बारीकी से पकड़ते हैं। उनकी कविताओं में रिश्तों में रिसाव, स्मृतियों की पीड़ा और आत्मिक बेचैनी बार-बार दिखाई देती है। लेकिन इन सबके बीच उम्मीद की एक धीमी लेकिन मजबूत रोशनी भी मौजूद रहती है। यही उनकी कविताओं को निराशा से बचाकर जीवन की ओर मोड़ती है। "मां और माटी" कविता इस संग्रह की महत्वपूर्ण रचनाओं में से एक है। भारतीय जीवन और संस्कृति में मां और मिट्टी दोनों का विशेष महत्व रहा है। मां जहां संवेदना, सुरक्षा और आत्मीयता का प्रतीक है, वहीं माटी मनुष्य की जड़ों, उसकी पहचान और उसकी संस्कृति का प्रतीक मानी जाती है। कविता की पंक्तियां — "मां और माटी की/ प्रायः बहस होती है/ नित्य प्रतिदिन/ कहीं दीप जले/ कहीं राग/ तो कहीं संगीत।" इन पंक्तियों में गांव, संस्कृति, परंपरा और जीवन की सहजता का पूरा संसार उपस्थित हो उठता है। कवि यहां केवल दृश्य रचना नहीं कर रहे, बल्कि उस सांस्कृतिक चेतना को अभिव्यक्त कर रहे हैं जो आधुनिकता की तेज रफ्तार में धीरे-धीरे कमजोर होती जा रही है। दिलीप कुमार पाण्डेय की कविताओं में सामाजिक दृष्टि भी अत्यंत स्पष्ट दिखाई देती है। वे समाज में मौजूद असमानताओं, विडंबनाओं और टूटते मानवीय मूल्यों को लेकर सजग हैं। लेकिन उनकी दृष्टि केवल आलोचनात्मक नहीं है। वे समाज की समस्याओं को बाहर खड़े होकर देखने के बजाय स्वयं को उसी समाज का हिस्सा मानकर अभिव्यक्ति देते हैं। यही कारण है कि उनकी कविताओं में एक आत्मीय विश्वसनीयता दिखाई देती है। वे पाठक पर विचार थोपते नहीं, बल्कि उसे सोचने और महसूस करने के लिए प्रेरित करते हैं। उनकी भाषा भी इस संग्रह की बड़ी शक्ति है। वे कठिन और दुरूह शब्दों के माध्यम से पाठक को प्रभावित करने का प्रयास नहीं करते। उनकी भाषा सरल, सहज और संवादधर्मी है। लेकिन यही सरलता उनकी कविताओं को अधिक प्रभावशाली बनाती है। उनकी कविताएं पढ़ते समय ऐसा लगता है जैसे कोई संवेदनशील व्यक्ति अपने जीवन के अनुभव साझा कर रहा हो। यही आत्मीयता पाठक को उनकी रचनाओं से जोड़ती है। संग्रह में कई कविताएं ऐसी हैं जो मनुष्य के भीतर की बेचैनी और सामाजिक तनावों को बहुत प्रभावी ढंग से सामने लाती हैं। आधुनिक जीवन की भागदौड़ में मनुष्य धीरे-धीरे अपनी संवेदनाओं से दूर होता जा रहा है। रिश्ते औपचारिक होते जा रहे हैं और आत्मीयता कम होती जा रही है। कवि इन बदलावों को केवल सामाजिक परिवर्तन के रूप में नहीं देखते, बल्कि उन्हें मनुष्य की आंतरिक त्रासदी के रूप में महसूस करते हैं। यही कारण है कि उनकी कविताएं व्यक्तिगत अनुभवों से निकलकर सामूहिक अनुभव का रूप ले लेती हैं। 'मैं समय हूं' समकालीन हिंदी कविता में इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह संग्रह केवल यथार्थ का चित्रण नहीं करता, बल्कि मनुष्य को अपने भीतर झांकने के लिए भी प्रेरित करता है। यह संग्रह पाठक को संवेदनशील बनाता है, उसे सोचने पर मजबूर करता है और जीवन की छोटी-छोटी बातों में छिपे गहरे अर्थों को समझने की दृष्टि देता है। दिलीप कुमार पाण्डेय ने अपनी कविताओं के माध्यम से यह सिद्ध किया है कि कविता आज भी मनुष्य की सबसे गहरी अनुभूतियों को अभिव्यक्त करने का सबसे प्रभावी माध्यम है। समकालीन साहित्य के इस शोर और तात्कालिकता के दौर में 'मैं समय हूं' जैसी कृति पाठक को ठहरकर सोचने का अवसर देती है। यह संग्रह केवल साहित्यिक उपलब्धि नहीं, बल्कि संवेदनाओं, संघर्षों और मानवीय अनुभवों का ऐसा दस्तावेज है जो लंबे समय तक पाठकों के मन में अपनी उपस्थिति बनाए रखता है। दिलीप कुमार पाण्डेय की कविताएं यह विश्वास जगाती हैं कि जब तक मनुष्य के भीतर संवेदनाएं जीवित हैं, तब तक कविता भी जीवित रहेगी और समय की धूल में दबे अनुभवों को शब्द देती रहेगी।

बंगाल की हिंसा है लोकतंत्र पर धब्बा और बड़ी चुनौती

पश्चिम बंगाल में हाल ही में सम्पन्न विधानसभा चुनावों के बाद जिस प्रकार हिंसा, हत्याओं, आगजनी और राजनीतिक प्रतिशोध की घटनाएं सामने आई हैं, उन्होंने केवल राज्य की शांति को ही नहीं, बल्कि भारतीय लोकतंत्र की आत्मा को भी आहत किया है। चुनाव लोकतंत्र का उत्सव माना जाता है, किंतु जब यह उत्सव हिंसा, भय और प्रतिशोध में बदल जाए तो यह केवल राजनीतिक असफलता नहीं, बल्कि सामाजिक और नैतिक पतन का संकेत बन जाता है। बंगाल की ताजा हिंसक घटनाएं इसी चिंता को सामने लाती हैं। चुनाव के दौरान छिटपुट घटनाओं को छोड़ दें तो मतदान अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न हुआ था। लेकिन परिणामों की घोषणा के बाद जिस प्रकार राजनीतिक दलों के समर्थक एक-दूसरे के खिलाफ आक्रामक हुए, उसने यह स्पष्ट कर दिया कि राजनीतिक प्रतिस्पर्धा अब वैचारिक संघर्ष न रहकर प्रतिशोध और वर्चस्व की लड़ाई बनती जा रही है। भाजपा और तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़पें, कई लोगों की हत्याएं और विशेष रूप से सुवेंदु अधिकारी के करीबी चंद्रनाथ रथ की हत्या ने पूरे घटनाक्रम को और अधिक गंभीर बना दिया। आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि आखिर लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह क्यों बची रहनी चाहिए? यह विडंबना है कि भारत, जिसने विश्व को अहिंसा, करुणा और "वसुधैव कुटुम्बकम्" का मंत्र दिया, आज वही देश राजनीतिक हिंसा के कारण अपनी छवि धूमिल करता दिखाई देता है। महात्मा गांधी ने राजनीति को नैतिकता और सेवा से जोड़ा था, लेकिन आज राजनीति सत्ता, प्रतिशोध और भय का माध्यम बनती जा रही है। बंगाल की हिंसा इस बीमारी का एक भयावह उदाहरण है। पश्चिम बंगाल का राजनीतिक इतिहास हिंसा से अछूता नहीं रहा है। वामपंथी शासन के लंबे दौर से लेकर तृणमूल कांग्रेस के शासनकाल तक राजनीतिक संघर्ष कई बार रक्तरंजित रूप में सामने आया। बूथ कब्जाने, विरोधियों को डराने, स्थानीय दबंगों और अपराधी तत्वों का राजनीतिक संरक्षण-ये सब बंगाल की राजनीति की कटु वास्तविकताएं रही हैं। सत्ता बदलती रही, लेकिन राजनीतिक संस्कृति में अपेक्षित परिवर्तन नहीं आ सका। यही कारण है कि चुनाव परिणामों के बाद भी हिंसा का वातावरण बनता है और आम नागरिक भय तथा असुरक्षा के बीच जीने को मजबूर होता है। दरअसल जब राजनीति विचार और जनसेवा से हटकर केवल सत्ता प्राप्ति का माध्यम बन जाती है, तब हिंसा उसका स्वाभाविक परिणाम बनती है। हार को लोकतांत्रिक विनम्रता से स्वीकार करने के बजाय प्रतिशोध का माध्यम बना लेना लोकतांत्रिक मूल्यों का अपमान है। यही कारण है कि चुनाव आयोग के स्पष्ट निर्देशों और विजय जुलूसों पर प्रतिबंध के बावजूद हिंसक घटनाएं हुईं। यह केवल प्रशासनिक विफलता नहीं, बल्कि राजनीतिक दलों की नैतिक विफलता भी है। ममता बनर्जी द्वारा चुनाव परिणामों पर सवाल उठाना और राजनीतिक टकराव को तीखा बनाना हो या भाजपा द्वारा आक्रामक राजनीतिक प्रतिक्रिया-दोनों पक्षों को आत्ममंथन करने की आवश्यकता है। लोकतंत्र में विपक्ष और सत्ता दोनों की जिम्मेदारी होती है कि वे जनता को शांति और संयम का संदेश दें। दुर्भाग्य से हमारे राजनीतिक दल अक्सर कार्यकर्ताओं की भावनाओं को नियंत्रित करने के बजाय उन्हें उकसाने का काम करते हैं। परिणामस्वरूप हिंसा सामान्य राजनीतिक व्यवहार का हिस्सा बनती जा रही है। सबसे अधिक पीड़ा इस बात की है कि राजनीतिक हिंसा की कीमत हमेशा आम जनता को चुकानी पड़ती है। जिन लोगों के घर जलते हैं, जिन परिवारों के सदस्य मारे जाते हैं, जिन छोटे व्यापारियों की दुकानें टूटती हैं, उनका राजनीति से कोई सीधा संबंध नहीं होता। वे केवल उस हिंसक मानसिकता के शिकार बनते हैं जो सत्ता को मानवता से ऊपर मानती है। यह प्रश्न गंभीरता से पूछा जाना चाहिए कि आखिर राजनीतिक दल हिंसा का सहारा क्यों लेते हैं? जबकि इतिहास गवाह है कि हिंसा कभी स्थायी समाधान नहीं देती। हिंसा केवल भय, अविश्वास और प्रतिशोध को जन्म देती है। जो दल हिंसा को हथियार बनाते हैं, वे अंततः जनता की नजरों में अपना नैतिक अधिकार खो देते हैं। राजनीति का उद्देश्य समाज को जोड़ना होना चाहिए, तोड़ना नहीं। आज भारत एक नए वैश्विक दौर में प्रवेश कर रहा है। दुनिया भारत को एक उभरती आर्थिक शक्ति, तकनीकी महाशक्ति और लोकतांत्रिक मॉडल के रूप में देख रही है। वर्ष 2047 तक जब भारत अपनी स्वतंत्रता के सौ वर्ष पूरे करेगा, तब हमारा लक्ष्य केवल आर्थिक विकास नहीं होना चाहिए, बल्कि एक ऐसे सभ्य और नैतिक राष्ट्र का निर्माण भी होना चाहिए जहां राजनीति का आधार अहिंसा, संवाद और संवेदनशीलता हो। यदि राजनीतिक दल नफरत, सांप्रदायिकता और हिंसा को अपना हथियार बनाए रखेंगे, तो विकसित भारत का सपना अधूरा रह जाएगा। भारत की सबसे बड़ी शक्ति उसकी सांस्कृतिक चेतना रही है। गौतम बुद्ध ने करुणा का संदेश दिया, महावीर ने अहिंसा को जीवन का सर्वोच्च मूल्य बताया, गांधी ने सत्य और अहिंसा के बल पर साम्राज्य को चुनौती दी। यह वही भारत है जिसने दुनिया को यह सिखाया कि मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति प्रेम और सह-अस्तित्व है। लेकिन आज राजनीतिक स्वार्थों और गैर-राजनीतिक आपराधिक तत्वों के कारण देश की छवि प्रभावित हो रही है। अपराधी मानसिकता के लोग राजनीतिक संरक्षण प्राप्त कर लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं। वे दल बदलते रहते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य केवल शक्ति और स्वार्थ की पूर्ति होता है। बंगाल की ताजा घटनाओं में भी ऐसे तत्वों की भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता। समाधान केवल प्रशासनिक कठोरता में नहीं, बल्कि राजनीतिक संस्कृति के परिवर्तन में निहित है। सबसे पहले सभी राजनीतिक दलों को सार्वजनिक रूप से हिंसा की निंदा करनी चाहिए और अपने कार्यकर्ताओं को संयम बरतने का स्पष्ट संदेश देना चाहिए। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को यह समझना होगा कि लोकतंत्र प्रतिद्वंद्विता का नहीं, सह-अस्तित्व का नाम है। दूसरा, कानून व्यवस्था को लेकर "जीरो टॉलरेंस" की नीति अपनानी होगी। कि

अभियान

श्रृंगवेरपुर : आस्था, समरसता और मर्यादा का अमर तीर्थ

भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक परंपरा में ऐसे अनेक तीर्थ स्थल हैं जो केवल पूजा-अर्चना के केंद्र नहीं, बल्कि भारतीय जीवन मूल्यों, सामाजिक समरसता और मानवीय संवेदनाओं के जीवंत प्रतीक भी हैं। उत्तर प्रदेश की पावन धरती पर स्थित तीर्थराज प्रयाग से लगभग पैंतालीस किलोमीटर दूर गंगा तट पर बसा श्रृंगवेरपुर ऐसा ही एक ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल है, जिसका उल्लेख रामायण, रामचरितमानस और अनेक पुराणों में मिलता है। यह केवल एक धार्मिक धाम नहीं, बल्कि भगवान श्रीराम के वनगमन, निषादराज गुह की मित्रता, केवट प्रसंग और माता सीता की आस्था से जुड़ा वह पावन स्थल है जहां से भारतीय संस्कृति ने सामाजिक समरसता, समानता और लोकमर्यादा का अमर संदेश दिया।

श्रृंगवेरपुर का नाम सुनते ही त्रेतायुग की वह भावपूर्ण कथा आंखों के सामने सजीव हो उठती है जब अयोध्या से वनवास के लिए निकले भगवान श्रीराम, माता सीता और लक्ष्मण यहां पहुंचे थे। उस समय यह स्थान निषादराज गुह की राजधानी हुआ करता था। गंगा के किनारे बसा यह नगर प्राकृतिक सौंदर्य, धार्मिक वातावरण और लोक संस्कृति का अद्भुत संगम था। मान्यता है कि अयोध्या से वनवास के लिए निकलने के बाद भगवान श्रीराम ने पहली बार यहीं रात्रि विश्राम किया था। आगे बढ़ने के लिए उन्हें गंगा नदी पार करनी थी, लेकिन उस समय गंगा अपने प्रचंड वेग में बह रही थी। ऐसे में श्रृंगवेरपुर केवल एक पड़ाव नहीं रहा, बल्कि श्रीराम के वनवास जीवन की शुरुआत का महत्वपूर्ण साक्षी बन गया।

श्रृंगवेरपुर का धार्मिक महत्व केवल वनवास प्रसंग तक सीमित नहीं है। इसका संबंध भगवान श्रीराम के जन्म से भी जुड़ा हुआ माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार अयोध्या के राजा दशरथ संतान सुख से वंचित थे। अनेक प्रयासों के बाद भी जब उन्हें संतान प्राप्ति नहीं हुई, तब कुलगुरु वशिष्ठ ने उन्हें प्रयाग क्षेत्र में स्थित श्रृंगी ऋषि के आश्रम जाने का परामर्श दिया। राजा दशरथ श्रृंगी ऋषि के आश्रम पहुंचे और उनसे पुत्र प्राप्ति की कामना व्यक्त की। इसके बाद श्रृंगी ऋषि ने श्रृंगवेरपुर में पुत्रेष्ठि यज्ञ का आयोजन कराया। इसी यज्ञ के फलस्वरूप राजा दशरथ को चार पुत्र — श्रीराम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न की प्राप्ति हुई। इस प्रकार श्रृंगवेरपुर भगवान श्रीराम के जन्म की कथा से भी जुड़ जाता है और उसका धार्मिक महत्व और अधिक बढ़ जाता है।

रामचरितमानस में श्रृंगवेरपुर का वर्णन अत्यंत मार्मिक और भावनात्मक ढंग से किया गया है। जब भगवान श्रीराम वनवास के लिए निकले तो उनके साथ माता सीता और अनुज लक्ष्मण भी थे। अयोध्या छोड़ने के बाद वे श्रृंगवेरपुर पहुंचे। जैसे ही निषादराज गुह को यह समाचार मिला कि प्रभु श्रीराम उनके राज्य में पधारे हैं, वह अत्यंत प्रसन्न हुए और फल-फूल तथा अन्य उपहार लेकर प्रभु के स्वागत के लिए पहुंचे। निषादराज ने भगवान श्रीराम से आग्रह किया कि वे उनके महल में विश्राम करें, लेकिन श्रीराम ने वनवासी जीवन की मर्यादा का पालन करते हुए विनम्रता से यह प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। इसके बाद निषादराज उन्हें एक सुरक्षित और स्वच्छ स्थान पर ले गए, जिसे आज रामचौरा के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि रामचौरा वही स्थान है जहां भगवान श्रीराम ने रात्रि विश्राम किया था। वहां स्थित शीशम के वृक्ष आज भी लोगों की श्रद्धा का केंद्र हैं। कहा जाता है कि इन्हीं वृक्षों के नीचे प्रभु श्रीराम, माता सीता और लक्ष्मण ने विश्राम किया था। आज भी श्रद्धालु वहां पहुंचकर उन वृक्षों की पूजा करते हैं और परिक्रमा लगाते हैं। यह दृश्य केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक नहीं, बल्कि उस सांस्कृतिक स्मृति का हिस्सा है जिसे भारतीय समाज हजारों वर्षों से अपने भीतर संजोए हुए है। श्रृंगवेरपुर का सबसे प्रसिद्ध और भावपूर्ण प्रसंग केवट संवाद माना जाता है। यह प्रसंग भारतीय समाज में समरसता, समानता और प्रेम का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करता है। जब भगवान श्रीराम गंगा पार करने के लिए नाविक को बुलाते हैं, तब वह तुरंत नाव लेकर नहीं आता। वह विनम्रता से कहता है कि उसने सुना है कि प्रभु के चरणों के स्पर्श से पत्थर भी नारी बन जाते हैं। उसकी नाव तो लकड़ी की है, जो पत्थर से भी अधिक कोमल है। यदि वह भी स्त्री बन गई तो उसकी आजीविका समाप्त हो जाएगी। इसलिए वह पहले प्रभु के चरण धोना चाहता है। भगवान श्रीराम सहजता से उसकी बात स्वीकार कर लेते हैं। इसके बाद केवट अत्यंत श्रद्धा और प्रेम से प्रभु के चरण धोता है और फिर उन्हें नाव में बैठाकर गंगा पार कराता है।

यह प्रसंग केवल भक्ति की कथा नहीं है, बल्कि सामाजिक समानता का महान संदेश भी देता है। भगवान श्रीराम ने केवट को कभी छोटा या निम्न नहीं माना। उन्होंने प्रेम और सम्मान के साथ उसकी भावना को स्वीकार किया। यही कारण है कि यह प्रसंग आज भी भारतीय समाज में सामाजिक समरसता और मानवीय सम्मान का प्रतीक माना जाता है। श्रृंगवेरपुर के निषाद समाज के लोग स्वयं को उसी केवट का वंशज मानते हैं और बड़े गर्व तथा श्रद्धा के साथ इस परंपरा को आगे बढ़ाते हैं।

गंगा पार करने के बाद का प्रसंग भी अत्यंत भावुक है। जब भगवान श्रीराम के पास केवट को उतराई देने के लिए कुछ नहीं था, तब माता सीता ने अपनी रत्नजड़ित मुदरी उतारकर प्रभु के हाथों पर रख दी। लेकिन केवट ने वह मुदरी लेने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि वह कोई मूल्य नहीं चाहता, बल्कि जब प्रभु वनवास से लौटेंगे तब जो कुछ देंगे, उसे प्रसाद मानकर स्वीकार करेगा। यह प्रसंग त्याग, प्रेम और निस्वार्थ भक्ति की सर्वोच्च भावना को व्यक्त करता है।

श्रृंगवेरपुर का एक अन्य महत्वपूर्ण प्रसंग माता सीता और मां गंगा से जुड़ा हुआ है। गंगा पार करने के बाद माता सीता ने हाथ जोड़कर मां गंगा से प्रार्थना की कि वे वनवास की यात्रा को सफल और सुरक्षित बनाएं तथा चौदह वर्षों बाद सकुशल अयोध्या लौटने का आशीर्वाद दें। मान्यता है कि मां गंगा ने उन्हें आशीर्वाद दिया था कि उनका मनोरथ अवश्य पूर्ण होगा। यह वही स्थान माना जाता है जहां माता सीता ने मां गंगा से प्रत्यक्ष संवाद किया था। इस कारण यह स्थल महिलाओं और परिवारों के लिए विशेष आस्था का केंद्र माना जाता है।

चौदह वर्ष के वनवास और लंका विजय के बाद जब भगवान श्रीराम पुष्पक विमान से अयोध्या लौट रहे थे, तब माता सीता ने उन्हें श्रृंगवेरपुर की याद दिलाई। उन्होंने कहा कि केवट की उतराई देना और मां गंगा की पूजा अभी शेष है। इसके बाद भगवान श्रीराम का पुष्पक विमान श्रृंगवेरपुर में उतरा। यहां उन्होंने मां गंगा की पूजा-अर्चना की और निषाद समाज को उपहार प्रदान किए। यह प्रसंग बताता है कि भगवान श्रीराम केवल मर्यादा पुरुषोत्तम ही नहीं, बल्कि अपने वचनों और संबंधों को निभाने वाले आदर्श पुरुष भी थे। आज भी श्रृंगवेरपुर लाखों श्रद्धालुओं और पर्यटकों की आस्था का केंद्र बना हुआ है। माघ मेला, कुंभ और महाकुंभ के अवसर पर यहां देश-विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। इसके अतिरिक्त प्रत्येक पूर्णिमा, अमावस्या, एकादशी, कार्तिक पूर्णिमा और आषाढ़ माह की सप्तमी पर यहां विशाल मेले का आयोजन होता है। लोग गंगा स्नान करते हैं, पूजा-अर्चना करते हैं और भगवान श्रीराम से जुड़े स्थलों के दर्शन करते हैं।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विकसित किया जा रहा श्रीराम वनगमन मार्ग भी श्रृंगवेरपुर के महत्व को और बढ़ा रहा है। यह मार्ग उन सभी स्थलों को जोड़ रहा है जहां-जहां भगवान श्रीराम वनवास के दौरान गए थे। इससे न केवल धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि नई पीढ़ी भी भारतीय संस्कृति और रामायण की परंपराओं से जुड़ सकेगी।

श्रृंगवेरपुर केवल एक तीर्थ स्थल नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति की आत्मा का जीवंत प्रतीक है। यहां भगवान श्रीराम और माता सीता ने जिस समरसता, प्रेम, करुणा और लोकमर्यादा का संदेश दिया, वह आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना त्रेतायुग में था। यह स्थान हमें सिखाता है कि समाज की वास्तविक शक्ति प्रेम, सम्मान और समानता में निहित होती है। यही कारण है कि गंगा तट पर बसा यह पावन धाम आज भी श्रद्धा, भक्ति और भारतीय संस्कृति की अमिट पहचान बना हुआ है।

RNI No. GJHIN/25/A2786 Printed, Published & Owned by RAGINI JIGNESHKUMAR VAGHELA and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002
and Published from B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424. Editor : JIGNESHKUMAR PATHABHAI VAGHELA
Regd.Office : B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424 Gujarat,India. Phone : (o) 7698333307 (M) 8485951747,7096333307
Email:navsarjansanskruti2016@gmail.com*navsarjansanskruti2016@yahoo.com*Website : www.navsarjansanskruti.com

वंदे मातरम् से शुरू हुआ तमिलनाडु का नया राजनीतिक अध्याय: विजय के शपथ ग्रहण में संदेश या रणनीति?

चेन्नई। तमिलनाडु की राजनीति में सत्ता परिवर्तन के साथ ही रविवार को एक नया राजनीतिक और सांस्कृतिक विमर्श भी सामने आया, जब राज्य के नए मुख्यमंत्री C. Joseph Vijay के शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत पूरे वंदे मातरम् गीत के साथ की गई। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में न केवल सत्ता का हस्तांतरण हुआ, बल्कि प्रतीकों और संदेशों की राजनीति भी स्पष्ट रूप से दिखाई दी।

कार्यक्रम की शुरुआत में राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम्' का पूर्ण संस्करण, उसके बाद राष्ट्रगान और फिर तमिलनाडु का राज्य गीत 'तमिल थाई वाझथु' गाया गया। यह क्रम अपने आप में राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बन गया, क्योंकि अब तक राज्य के औपचारिक आयोजनों में राज्य गीत को प्राथमिकता दी जाती रही है।

शपथ ग्रहण समारोह में यह भी देखा गया कि बड़ी संख्या में समर्थकों की मौजूदगी, भव्य मंच व्यवस्था और राजनीतिक हस्तियों की भागीदारी ने इस आयोजन को एक सामान्य शपथ ग्रहण से कहीं अधिक एक शक्ति प्रदर्शन में बदल दिया। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर यह चर्चा तेज हो गई है कि क्या यह केवल औपचारिकता थी या फिर इसके पीछे एक स्पष्ट राजनीतिक संदेश छिपा हुआ था।

विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी के दृष्टिकोण से इसे जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि हाल के वर्षों में राष्ट्रीय स्तर पर वंदे मातरम् के पूर्ण पाठ को लेकर राजनीतिक और वैचारिक बहसें तेज रही हैं। ऐसे में विजय के शपथ ग्रहण में इसकी शुरुआत को कई विश्लेषक एक प्रतीकात्मक संकेत के रूप में देख रहे हैं, जिसका उद्देश्य केंद्र की राजनीति के साथ एक संतुलित संबंध दिखाना हो सकता है।

हालांकि इस कार्यक्रम में विपक्ष के कई नेता भी मौजूद रहे, जिनमें कांग्रेस नेता Rahul Gandhi की उपस्थिति विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करने

वाली रही। मंच पर उनकी मौजूदगी ने इस आयोजन को राष्ट्रीय राजनीतिक विमर्श से भी जोड़ दिया।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि विजय की नई सरकार अपने शुरुआती कदमों से ही यह संदेश देने की कोशिश कर रही है कि वह केवल क्षेत्रीय पहचान तक सीमित नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय प्रतीकों और भावनाओं को भी महत्व देती है। वंदे मातरम्, राष्ट्रगान और राज्य गीत का क्रम इसी संतुलन की ओर संकेत करता है।

हालांकि, इस पर राजनीतिक विवाद भी शुरू हो गया है। कुछ आलोचकों का कहना है कि राज्य की सांस्कृतिक पहचान को प्राथमिकता देने के बजाय राष्ट्रीय प्रतीकों पर अधिक जोर देना एक राजनीतिक रणनीति का हिस्सा हो सकता है। वहीं समर्थक इसे एकता और राष्ट्रीय समन्वय का प्रतीक मान रहे हैं।

इसी बीच यह भी ध्यान देने योग्य है कि पिछले कुछ दिनों में राष्ट्रीय गीत को लेकर केंद्र और विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच बयानबाजी तेज रही है। ऐसे में विजय का यह कदम एक "मध्य मार्ग" की तरह देखा जा रहा है, जिसमें उन्होंने राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दोनों भावनाओं को साथ रखने का प्रयास किया है।

समारोह के दौरान एक और महत्वपूर्ण पहलू यह रहा कि विजय ने अपने भाषण में सामाजिक न्याय, पारदर्शिता और विकास को अपनी सरकार की प्राथमिकता बताया। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी सरकार किसी एक विचारधारा या समूह के बजाय पूरे राज्य की सरकार होगी।

राजनीतिक हलकों में यह भी चर्चा है कि यह पूरा आयोजन केवल एक शपथ ग्रहण नहीं, बल्कि एक राजनीतिक संदेशों से भरा मंच था, जिसमें प्रतीकों, गीतों और उपस्थिति के माध्यम से कई स्तरों पर संकेत दिए गए। खासकर भाजपा के संदर्भ में इसे लेकर अलग-अलग व्याख्याएं सामने आ रही हैं कि क्या यह समर्थन का संकेत है या राजनीतिक संतुलन की रणनीति।

दूसरी ओर, पश्चिम बंगाल में हाल ही में हुए एक अन्य शपथ ग्रहण कार्यक्रम का भी उल्लेख इस संदर्भ में किया जा रहा है, जहां वंदे मातरम् को लेकर समान विवाद और चर्चा देखने को मिली थी। इससे यह संकेत मिलता है कि राष्ट्रीय प्रतीकों को लेकर राजनीति अब राज्यों की राजनीति में भी गहराई से प्रवेश कर चुकी है।

कुल मिलाकर, तमिलनाडु का यह शपथ ग्रहण समारोह केवल सत्ता परिवर्तन का क्षण नहीं था, बल्कि यह एक नए राजनीतिक संदेश की शुरुआत भी माना जा रहा है। Tamilaga Vettri Kazhagam की सरकार के सामने अब चुनौती केवल शासन चलाने की नहीं, बल्कि इस बहुस्तरीय राजनीतिक प्रतीकों और अपेक्षाओं के बीच संतुलन बनाने की भी होगी।

आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि यह "वंदे मातरम् से शुरू हुआ युग" वास्तव में एक नए राजनीतिक दृष्टिकोण की शुरुआत है या केवल एक औपचारिक प्रतीकात्मक कदम।

"मैं 90% सोशल वर्क करता हूं", गडकरी का जल संकट पर बड़ा संदेश : पानी बचाने को बताया देश की सबसे बड़ी जरूरत

नागपुर/पुणे। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री Nitin Gadkari ने एक बार फिर अपने बयानों और सामाजिक अभियानों को लेकर सुर्खियां बटोरी हैं। उन्होंने कहा है कि उनका अधिकांश समय राजनीति नहीं बल्कि सामाजिक कार्यों में जाता है और यही कारण है कि उन्हें पारंपरिक चुनावी प्रचार पर अधिक निर्भर नहीं रहना पड़ता।

पुणे में आयोजित एक कार्यक्रम में, जहां उद्योगपति अभय फिरोदिया को 'पुण्य भूषण' सम्मान से नवाजा गया, गडकरी ने कहा कि वे स्वयं को एक ऐसे जनप्रतिनिधि के रूप में देखते हैं जो समाज के विकास के लिए लगातार काम करता है। उन्होंने कहा कि उनका लगभग 90 प्रतिशत काम सामाजिक गतिविधियों, विशेषकर जल संरक्षण और ग्रामीण विकास से जुड़ा हुआ है।

गडकरी के इस बयान ने एक बार फिर राजनीति और सामाजिक कार्य के बीच संतुलन को लेकर बहस छेड़ दी है। उन्होंने यह भी कहा कि नैतिकता आधारित व्यवसाय और सामाजिक जिम्मेदारी समय की जरूरत है, और उद्योग जगत को भी समाज के प्रति संवेदनशील होना चाहिए।

इसी कार्यक्रम के बाद नागपुर में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने देश के सामने खड़े सबसे बड़े संकटों में जल संकट को प्रमुखता से रखा। उन्होंने कहा कि भारत में पानी की कमी वास्तविक समस्या नहीं है, बल्कि समस्या उसके प्रबंधन और वितरण की है। अगर पानी का सही नियोजन किया जाए तो देश के कई सूखे और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति बदली जा सकती है।

विदर्भ क्षेत्र का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि यहां किसानों की आत्महत्याओं का एक बड़ा कारण जल संकट और

सिंचाई सुविधाओं की कमी है। यह समस्या केवल आर्थिक नहीं बल्कि सामाजिक और पर्यावरणीय भी है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सरकार के साथ-साथ समाज को भी जल संरक्षण की दिशा में सक्रिय भूमिका निभानी होगी।

गडकरी ने बताया कि उनकी संस्था Purtisnchan Samruddhi Kalyankari Sanstha पिछले 25 वर्षों से जल संरक्षण और किसानों की आय बढ़ाने के लिए काम कर रही है। इस संस्था ने छोटे-छोटे स्तर पर जल संरचनाओं के निर्माण से लेकर बड़े जल प्रबंधन मॉडल तक कई प्रयोग किए हैं।

उन्होंने देश में एक "वॉटर ग्रिड" मॉडल की आवश्यकता पर जोर दिया। उनके अनुसार जिस तरह देश में हाईवे और पावर ग्रिड नेटवर्क बनाए गए हैं, उसी तरह एक राष्ट्रीय जल ग्रिड भी तैयार किया जाना चाहिए। इस मॉडल के तहत बाढ़ वाले क्षेत्रों के अतिरिक्त पानी को पाइपलाइन और नहरों के माध्यम से सूखे इलाकों तक पहुंचाया जा सकता है। इससे एक तरफ बाढ़ की समस्या कम होगी और दूसरी तरफ सूखे क्षेत्रों को पानी मिलेगा। गडकरी ने यह भी कहा कि जल संरक्षण को केवल सरकारी योजना के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि इसे एक जन आंदोलन बनाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि अगर गांव, पंचायत और स्थानीय समुदाय इस अभियान में जुड़ें तो परिणाम कहीं अधिक प्रभावी होंगे।

अपने भाषण में उन्होंने कई सफल स्थानीय मॉडलों का भी उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि उनके प्रयासों से Dr. Panjabrao Deshmukh Krishi Vidyapeeth के सहयोग से 350 से अधिक तालाबों का निर्माण किया गया, जिससे भूजल स्तर में सुधार हुआ और सिंचाई क्षमता बढ़ी।

इन तालाबों की खुदाई से निकली मिट्टी का उपयोग सड़क निर्माण में किया गया, जिससे संसाधनों का पुनः उपयोग संभव हुआ। इस मॉडल को बाद में 'बुलढाणा पैटर्न' के नाम से जाना जाने लगा और इसे देश के अन्य हिस्सों में भी अपनाने पर चर्चा हुई। उन्होंने 'तमसवाड़ा रिजुविनेशन मॉडल' का भी उल्लेख किया, जिसके तहत धुले जिले में लगभग समाप्त हो चुके 12 किलोमीटर लंबे नाले को पुनर्जीवित किया गया। यह परियोजना वैज्ञानिक अध्ययन और भूवैज्ञानिक विशेषज्ञों की मदद से तैयार की गई थी और इसका उद्देश्य वर्षा जल को संरक्षित करना और स्थानीय जल स्तर को सुधारना था।

गडकरी ने कहा कि ऐसे छोटे लेकिन प्रभावी मॉडल पूरे देश में लागू किए जा सकते हैं, जिससे बड़े स्तर पर जल संकट को नियंत्रित किया जा सकता है।

नागपुर में आयोजित होने वाले आगामी 'जल संवाद' और 'जलक्रांति परिषद' की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि यह कार्यक्रम 17 और 18 मई को आयोजित किया जाएगा। इसमें समाज, उद्योग और कला जगत की कई प्रमुख हस्तियां शामिल होंगी, जिनमें Nana Patekar, Aamir Khan और मकरंद अनासपुरे जैसे नाम शामिल हैं।

इस आयोजन का उद्देश्य जल संरक्षण को जन-जन तक पहुंचाना और इसे एक सामाजिक अभियान का रूप देना है। गडकरी ने उम्मीद जताई कि यदि समाज एकजुट होकर जल संरक्षण के लिए काम करे तो आने वाले वर्षों में भारत जल संकट जैसी गंभीर समस्या से काफी हद तक मुक्त हो सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि जल ही जीवन है और यदि पानी का संरक्षण नहीं किया गया तो आने वाली पीढ़ियों के लिए गंभीर संकट खड़ा हो सकता है। इसलिए अब समय आ गया है कि सरकार, समाज और उद्योग तीनों मिलकर इस दिशा में ठोस कदम उठाएं। कुल मिलाकर, गडकरी का यह संदेश केवल एक राजनीतिक बयान नहीं बल्कि एक व्यापक सामाजिक अपील के रूप में देखा जा रहा है, जिसमें विकास, पर्यावरण और ग्रामीण जीवन तीनों को एक साथ जोड़ने की कोशिश दिखाई देती है।

'वन नेशन, वन स्टैंडर्ड' के तहत बड़ा सुधार: देशभर के 71 हजार अस्पतालों में आईसीयू के लिए पहली बार समान मानक लागू

नई दिल्ली। भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था में एक बड़ा संरचनात्मक बदलाव करते हुए केंद्र सरकार ने गहन चिकित्सा इकाइयों (ICU) के लिए पहली बार देशव्यापी समान मानक तय कर दिए हैं। इस फैसले को 'वन नेशन, वन स्टैंडर्ड' की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है, जिसका सीधा असर देश के करीब 71,000 अस्पतालों पर पड़ेगा। इसके साथ ही 13.8 लाख से अधिक पंजीकृत डॉक्टर भी नए दिशा-निर्देशों के दायरे में आएंगे।

स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशालय (DGHS) ने इन नए मानकों को जारी किया है, जिसके तहत अब देशभर के सभी आईसीयू को तीन श्रेणियों में विभाजित किया जाएगा। इन श्रेणियों में बिस्तरों की संख्या, उपकरणों की उपलब्धता, डॉक्टरों की योग्यता और नर्सिंग स्टाफ की न्यूनतम आवश्यकता को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है।

सरकार का मानना है कि इस पहल से देश में गंभीर मरीजों के इलाज में एकरूपता आएगी और विभिन्न राज्यों व अस्पतालों के बीच मौजूद असमानता को काफी हद तक कम किया जा सकेगा। अब तक आईसीयू सुविधाएं अस्पताल दर अस्पताल अलग-अलग मानकों पर संचालित होती थीं, जिससे कई बार मरीजों को उचित और समय पर इलाज नहीं मिल पाता था।

विशेषज्ञों के अनुसार, कोविड-19 महामारी के दौरान यह असमानता और भी स्पष्ट रूप से सामने आई थी, जब कई जगहों पर ऑक्सीजन, वेंटिलेटर और प्रशिक्षित स्टाफ की भारी कमी देखी गई। इस अनुभव ने सरकार

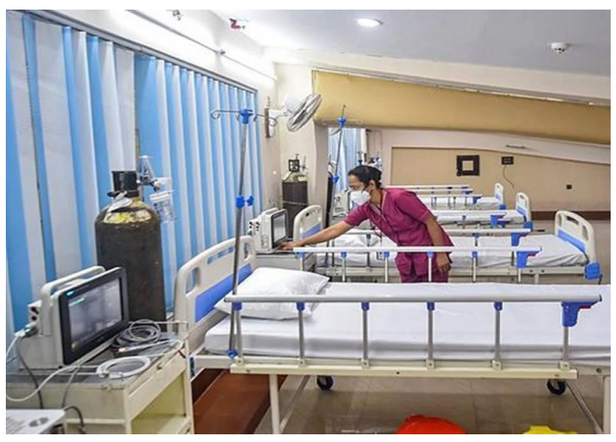

को स्वास्थ्य ढांचे में व्यापक सुधार की दिशा में सोचने के लिए मजबूर किया।

नए दिशा-निर्देशों के तहत अस्पतालों की भौतिक संरचना पर भी स्पष्ट नियम तय किए गए हैं। आईसीयू को अब आपातकालीन विभाग और ऑपरेशन थिएटर के नजदीक स्थापित करना अनिवार्य किया गया है, ताकि गंभीर मरीजों को बिना देरी के उपचार मिल सके। प्रत्येक बिस्तर पर मल्टीपैरामीटर मॉनिटर की व्यवस्था भी अनिवार्य होगी, जिससे मरीज की स्थिति की लगातार निगरानी की जा सके।

इसके अलावा, स्तर-3 आईसीयू में उन्नत चिकित्सा उपकरणों जैसे पोर्टेबल सीटी स्कैन और मोबाइल डिजिटल एक्स-रे मशीनों की उपलब्धता को भी आवश्यक बताया गया है। यह स्तर विशेष रूप से उन मरीजों के लिए होगा, जिनकी स्थिति अत्यंत गंभीर होती है और जिन्हें मल्टी-ऑर्गन फेल्योर जैसी जटिल स्थितियों का सामना करना पड़ता है।

नई व्यवस्था के अनुसार, आईसीयू को तीन स्तरों में विभाजित किया गया है। स्तर-1 आईसीयू छोटे अस्पतालों में शुरुआती आपातकालीन देखभाल के लिए होंगे, जहां न्यूनतम छह बिस्तरों और एक वेंटिलेटर की सुविधा आवश्यक होगी। इनका उद्देश्य मरीज को स्थिर करना और आगे के इलाज के लिए रेफर करना होगा।

स्तर-2 आईसीयू में कम से कम आठ बिस्तर होंगे और इनमें केंद्रीय ऑक्सीजन प्रणाली के साथ-साथ आधे बिस्तरों पर वेंटिलेटर की सुविधा अनिवार्य होगी। इसके साथ ही किडनी से जुड़ी आपातकालीन चिकित्सा सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी।

सबसे उन्नत स्तर यानी स्तर-3 आईसीयू में अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इन आईसीयू को उच्च जोखिम वाले मरीजों के लिए तैयार किया गया है, जहां लगातार निगरानी और उन्नत उपचार संभव हो सकेगा।

डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ के लिए भी नए मानक लागू किए गए हैं। सभी आईसीयू में 24 घंटे डॉक्टरों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। विशेष रूप से स्तर-2 और स्तर-3 आईसीयू में विशेषज्ञ डॉक्टरों के लिए डीएम या डीएनबी जैसी उच्च डिग्री की शर्त रखी गई है। हालांकि लंबे समय से आईसीयू में कार्यरत अनुभवी डिप्लोमा धारकों को भी कुछ परिस्थितियों में मान्यता दी गई है।

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, देश में सार्वजनिक क्षेत्र में मेडिकल कॉलेजों और जिला अस्पतालों को मिलाकर लगभग 37,834 आईसीयू बेड पहले से मौजूद हैं। इनमें पहाड़ी और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में बनाए गए विशेष गंभीर चिकित्सा ब्लॉक भी शामिल हैं। लेकिन अब तक इन सभी की गुणवत्ता और सुविधाओं में एकरूपता नहीं थी।

नए मानकों के लागू होने के बाद अस्पतालों में संक्रमण नियंत्रण, उपकरणों की गुणवत्ता और चिकित्सा सेवाओं की पारदर्शिता में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है। इसके साथ ही मरीजों और उनके परिजनों को भी यह स्पष्ट जानकारी मिलेगी कि संबंधित अस्पताल किस स्तर की चिकित्सा सुविधा प्रदान कर सकता है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि यह सुधार भारतीय स्वास्थ्य प्रणाली को एक नई दिशा दे सकता है। इससे न केवल शहरी बल्कि ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में भी गंभीर मरीजों के इलाज की गुणवत्ता में सुधार होगा।

कुल मिलाकर, यह निर्णय भारत में स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक संगठित, मानकीकृत और आधुनिक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जिससे आने वाले वर्षों में आईसीयू सेवाओं की गुणवत्ता में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है।

एक कार्ड से पूरे देश का सफर: DMRC ने लॉन्च किया RuPay 'On-The-Go' NCMC कार्ड, डिजिटल ट्रैवल में बड़ा बदलाव

नई दिल्ली। भारत में सार्वजनिक परिवहन को पूरी तरह डिजिटल और एकीकृत बनाने की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए Delhi Metro ने एयरटेल पेमेंट्स बैंक के साथ मिलकर RuPay 'On-The-Go' नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (NCMC) लॉन्च कर दिया है। इस नई पहल को देश के ट्रैवल और पेमेंट सिस्टम में "वन कार्ड, वन देश" मॉडल की दिशा में बड़ा परिवर्तन माना जा रहा है।

इस लॉन्च के साथ ही यात्रियों को अब अलग-अलग शहरों और परिवहन सेवाओं के लिए अलग-अलग कार्ड या टिकट सिस्टम की जरूरत नहीं होगी। एक ही कार्ड से मेट्रो, बस, पार्किंग और अन्य सार्वजनिक परिवहन सेवाओं में भुगतान संभव होगा।

कार्यक्रम में दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक डॉ. विकास कुमार और एयरटेल पेमेंट्स बैंक के CEO अनुब्रत बिस्वास सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। दोनों संस्थानों ने इसे डिजिटल इंडिया और स्मार्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया।

यह नया कार्ड RuPay नेटवर्क पर आधारित है और नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (NCMC) तकनीक से लैस है। इसका मतलब यह है कि यह एक ओपन-लूप पेमेंट सिस्टम की तरह काम करेगा, जहां यात्री इसे देशभर के विभिन्न ट्रांसपोर्ट नेटवर्क पर बिना किसी प्रतिबंध के इस्तेमाल कर सकेंगे।

फिलहाल दिल्ली मेट्रो में उपयोग किए जाने वाले कार्ड केवल सीमित नेटवर्क तक ही मान्य होते हैं, लेकिन नया NCMC कार्ड पूरे देश में इंटरऑपरेबल होगा। यानी यह सिर्फ दिल्ली मेट्रो तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, लखनऊ और अन्य शहरों के मेट्रो नेटवर्क में भी इस्तेमाल किया जा सकेगा।

इस पहल को केंद्र सरकार के महत्वाकांक्षी 'One Nation, One Card' मिशन का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य देशभर में ट्रांसपोर्ट और डिजिटल पेमेंट सिस्टम को एकीकृत करना है ताकि यात्रियों को अलग-अलग शहरों में अलग-अलग कार्ड या ऐप की जरूरत न पड़े।

नई व्यवस्था के तहत यात्रियों को कार्ड रिचार्ज करने के लिए अब लंबी कतारों में खड़े होने की जरूरत भी नहीं होगी। यह कार्ड DMRC ऐप या एयरटेल पेमेंट्स बैंक के डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से कभी भी ऑनलाइन रिचार्ज किया जा सकेगा।

DMRC के अनुसार, आने वाले 10 दिनों के भीतर ये नए कार्ड सभी मेट्रो स्टेशनों पर उपलब्ध करा दिए जाएंगे। शुरुआती चरण में यात्रियों को पुराने कार्ड के साथ-साथ नया NCMC कार्ड भी इस्तेमाल करने का विकल्प मिलेगा। इस पहल का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि यात्रियों को निर्बाध यात्रा अनुभव मिलेगा। चाहे वह दिल्ली मेट्रो हो या किसी अन्य शहर का सार्वजनिक परिवहन, एक ही कार्ड से भुगतान संभव होगा। इससे समय की बचत होगी और कैशलेस ट्रांजेक्शन को भी बढ़ावा मिलेगा।

DMRC के एमडी डॉ. विकास कुमार ने कहा कि यह पहल केवल एक तकनीकी अपग्रेड नहीं है, बल्कि यह यात्रियों के अनुभव को पूरी तरह बदलने वाली व्यवस्था है। उनके अनुसार, इससे ट्रांसपोर्ट सिस्टम अधिक स्मार्ट, तेज और उपयोगकर्ता-अनुकूल बनेगा।

वहीं एयरटेल पेमेंट्स बैंक के CEO अनुब्रत बिस्वास ने कहा कि यह साझेदारी डिजिटल फर्स्ट ट्रांजिट इकोसिस्टम को मजबूत करेगी और भारत को एकीकृत भुगतान प्रणाली की ओर तेजी से ले जाएगी।

इस कार्ड की एक खास बात यह भी है कि यह डेबिट कार्ड और प्रीपेड ट्रांजिट कार्ड दोनों के रूप में काम करेगा। यानी यात्री इसे बैंकिंग ट्रांजेक्शन के साथ-साथ यात्रा भुगतान के लिए भी इस्तेमाल कर सकेंगे।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम भारत में डिजिटल पेमेंट और स्मार्ट ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के बीच एक मजबूत पुल का काम करेगा। इससे न केवल यात्रियों को सुविधा मिलेगी, बल्कि ट्रांजेक्शन सिस्टम भी अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनेगा।

यह भी माना जा रहा है कि भविष्य में इस कार्ड को और अधिक सेवाओं जैसे ई-रिक्शा, टैक्सी, पार्किंग और टोल भुगतान से भी जोड़ा जा सकता है, जिससे यह एक पूर्ण डिजिटल मोबिलिटी समाधान बन सकता है।

कुल मिलाकर, RuPay 'On-The-Go' NCMC कार्ड का लॉन्च भारत के शहरी परिवहन को एक नई दिशा देने वाला कदम है, जो यात्रियों के लिए सफर को न केवल आसान बल्कि पूरी तरह डिजिटल और एकीकृत अनुभव में बदलने की क्षमता रखता है।

‘अजन्मा भी इंसान है’ — कीम स्टेशन हादसे में गुजरात हाई कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, मानव अधिकारों की नई परिभाषा तय

सूरत। न्यायपालिका ने एक बार फिर मानवता और कानून की सीमाओं को नए दृष्टिकोण से परिभाषित करते हुए एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। Kim Railway Station पर वर्ष 2018 में हुए दर्दनाक रेल हादसे से जुड़े मामले में Gujarat High Court ने यह स्पष्ट कर दिया है कि गर्भ में पल रहा अजन्मा बच्चा भी कानूनी रूप से ‘व्यक्ति’ माना जा सकता है और उसे मुआवजे का अधिकार प्राप्त है।

यह निर्णय न केवल रेलवे दुर्घटना से जुड़े एक मामले का निपटारा है, बल्कि भारतीय कानूनी इतिहास में एक ऐसा मोड़ भी माना जा रहा है, जहां जीवन की शुरुआत को लेकर न्यायिक सोच और अधिक संवेदनशील और विस्तृत हुई है।

यह मामला मध्य प्रदेश निवासी जयप्रकाश घसीटालाल से जुड़ा है, जो अपनी गर्भवती पत्नी उषाबेन और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ 14 अप्रैल 2018 को कानपुर जाने के लिए कीम रेलवे स्टेशन पहुंचे थे। ट्रेन में चढ़ने के दौरान हुए हादसे में नौ महीने की गर्भवती उषाबेन की मौत हो गई थी। इस दुर्घटना में गर्भ में पल रहे बच्चे की भी मृत्यु हो गई थी।

इस दर्दनाक घटना के बाद परिवार ने रेलवे क्लेम ट्रिब्यूनल में दो अलग-अलग मुआवजा दावे प्रस्तुत किए। ट्रिब्यूनल ने महिला की मृत्यु के लिए 8 लाख रुपये का मुआवजा तो मंजूर कर दिया, लेकिन अजन्मे बच्चे के लिए किसी प्रकार के मुआवजे से इनकार कर दिया था। ट्रिब्यूनल का तर्क था कि कानून की मौजूदा व्याख्या के अनुसार भ्रूण को ‘व्यक्ति’ की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता।

इस फैसले को चुनौती देते हुए परिवार ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। अदालत में याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता नितिन कपाड़े ने जोरदार दलीलें पेश कीं। उन्होंने कहा कि गर्भ में 5 महीने से अधिक विकसित भ्रूण केवल एक जैविक संरचना नहीं है, बल्कि वह जीवन का एक विकसित रूप है, जिसे कानून और मानवता दोनों के दृष्टिकोण से अलग पहचान मिलनी चाहिए।

मामले की विस्तृत सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति जे.सी. दोशी ने इस तर्क को गंभीरता से सुना और कई कानूनी एवं नैतिक पहलुओं पर विचार किया। अदालत ने अपने निर्णय में कहा कि जीवन की अवधारणा केवल जन्म के बाद शुरू नहीं होती, बल्कि गर्भावस्था के दौरान भी एक स्वतंत्र अस्तित्व विकसित होता है, जिसे नकारा नहीं जा सकता।

अदालत ने यह भी माना कि आधुनिक चिकित्सा विज्ञान और कानूनी व्याख्या दोनों इस बात की पुष्टि करते हैं कि भ्रूण एक विकसित जीवन का हिस्सा होता है। ऐसे में उसे पूरी तरह कानूनी अधिकारों से वंचित रखना न्यायसंगत नहीं है।

इस ऐतिहासिक निर्णय के तहत अदालत ने रेलवे प्रशासन को आदेश दिया कि वह तीन सप्ताह के भीतर मृतका के पति को 9 प्रतिशत ब्याज सहित 8 लाख रुपये का अतिरिक्त मुआवजा अदा करे। यह राशि विशेष रूप से अजन्मे बच्चे की क्षति के लिए मानी गई है।

इस फैसले के बाद कानूनी और सामाजिक हलकों में व्यापक चर्चा शुरू हो गई है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि यह निर्णय भारत में अजन्मे बच्चों के अधिकारों को लेकर एक नई कानूनी दिशा तय कर सकता है। अब तक भारतीय कानून में भ्रूण को सीमित परिस्थितियों में ही अधिकार दिए जाते थे, लेकिन इस फैसले ने उस परिभाषा को विस्तृत कर दिया है।

कानूनी जानकारों का कहना है कि यह मामला केवल मुआवजे तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भविष्य में जीवन के अधिकार (Right to Life) की व्याख्या को भी प्रभावित कर सकता है। इससे पहले विभिन्न देशों में भी ऐसे निर्णय सामने आ चुके हैं, जहां भ्रूण को सीमित कानूनी पहचान दी गई है, लेकिन भारत में यह पहला स्पष्ट और मजबूत न्यायिक आदेश माना जा रहा है।

यह मामला मानवीय संवेदनाओं से भी गहराई से जुड़ा हुआ है। एक तरफ यह एक रेलवे दुर्घटना का दुखद प्रसंग है, वहीं दूसरी ओर यह उस परिवार के दर्द को भी दर्शाता है जिसने एक ही क्षण में मां और अजन्मे बच्चे दोनों को खो दिया।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला भविष्य में बीमा, मुआवजा और आपदा कानूनों में भी बदलाव की नींव रख सकता है। अब तक कई मामलों में अजन्मे बच्चों के लिए मुआवजे को लेकर अस्पष्टता रही है, लेकिन इस निर्णय के बाद कानूनी स्पष्टता बढ़ने की संभावना है।

कुल मिलाकर, गुजरात हाई कोर्ट का यह फैसला न केवल एक न्यायिक आदेश है, बल्कि यह जीवन, अधिकार और मानवता की नई व्याख्या भी प्रस्तुत करता है। यह निर्णय इस बात को रेखांकित करता है कि कानून केवल नियमों का संग्रह नहीं, बल्कि समाज की संवेदनाओं और मानवीय मूल्यों का भी प्रतिबिंब है।

सूरत में नेतृत्व, सेवा और जवाबदेही का संदेश राजनीति में पद नहीं, जनसेवा ही असली पहचान

सूरत में आयोजित एक जनसेवा एवं सम्मान कार्यक्रम ने स्थानीय राजनीति में सेवा, अनुशासन और जवाबदेही को लेकर एक बार फिर गंभीर बहस को जन्म दिया। इस कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने नवनिर्वाचित पार्षदों और पार्टी पदाधिकारियों को स्पष्ट शब्दों में याद दिलाया कि जनप्रतिनिधि का पद किसी व्यक्तिगत सम्मान या शक्ति का प्रतीक नहीं, बल्कि जनता की सेवा का एक अवसर है। उनके संबोधन का मूल संदेश यही था कि राजनीति में स्थायित्व केवल लोकप्रियता या सत्ता से नहीं, बल्कि जनता के विश्वास और व्यवहार की गुणवत्ता से तय होता है।

कार्यक्रम का माहौल औपचारिक होने के बावजूद भावनात्मक था, क्योंकि इसमें सत्ता और सेवा के बीच संतुलन की सीख दी जा रही थी। हर्ष संघवी ने मंच से कहा कि कई लोग चुनाव जीतने के बाद यह भूल जाते हैं कि वे जनता के प्रतिनिधि हैं, न कि किसी विशेष वर्ग या स्वार्थ के। उन्होंने साफ कहा कि “पांच साल का कार्यकाल बहुत छोटा होता है, लेकिन इस दौरान किया गया व्यवहार लंबे समय तक याद रखा जाता है।”

कार्यक्रम में मौजूद पार्षदों, पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की बड़ी भीड़ इस संदेश को गंभीरता से सुनती नजर आई। संघवी ने यह भी कहा कि संगठन और जनता दोनों ही किसी भी जनप्रतिनिधि के काम का मूल्यांकन करते हैं और गलत व्यवहार या लापरवाही का परिणाम राजनीतिक जीवन में देर-सबेर सामने आता है। उनका यह संदेश स्पष्ट रूप से सत्ता के अहंकार के खिलाफ एक चेतावनी के रूप में देखा गया।

इस आयोजन की एक विशेष बात यह रही कि उप मुख्यमंत्री ने परंपरागत प्रोटोकॉल से हटकर उपहार वितरण में पारदर्शिता और सामूहिकता को प्राथमिकता दी। उन्होंने अपने पास आए उपहारों को अपने पास रखने के बजाय कार्यकर्ताओं और नागरिकों के बीच वितरित करने की पहल की। कार्यक्रम में बुजुर्गों को विशेष सम्मान दिया गया और उपहार वितरण की जिम्मेदारी भी उन्हीं को सौंपी गई। इस दौरान कैलाशजी सहित पांच बुजुर्गों ने ड्रॉ सिस्टम के माध्यम से विजेताओं का चयन किया, जिससे प्रक्रिया में निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित की गई।

हर्ष संघवी ने इस पहल को प्रतीकात्मक बताते हुए कहा कि सार्वजनिक जीवन में किसी भी प्रकार का भेदभाव या पक्षपात स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। उनका मानना था कि जनप्रतिनिधियों को अपने निर्णय और व्यवहार में पूरी तरह पारदर्शी रहना चाहिए ताकि जनता का भरोसा मजबूत बना रहे।

अपने संबोधन में उन्होंने पार्षदों को यह भी समझाया कि पद मिलने के बाद व्यक्ति को अपने मन से यह भावना निकाल देनी चाहिए कि वह विशेष है। उन्होंने कहा कि वास्तविक नेतृत्व वही है जो आम नागरिकों के बीच रहकर उनकी समस्याओं को समझे और समाधान की दिशा में काम करे। उनके अनुसार, राजनीति में सबसे बड़ी परीक्षा सत्ता प्राप्त करना नहीं, बल्कि उसे संभालते हुए जनता के प्रति ईमानदार रहना है।

कार्यक्रम के दौरान उन्होंने अपने व्यस्त कार्यक्रमों के कारण कार्यकर्ताओं से व्यक्तिगत रूप से न मिल पाने पर सार्वजनिक रूप से माफी भी मांगी, जो उनके भाषण का एक भावनात्मक हिस्सा रहा। उन्होंने कहा कि उन्हें मिले सम्मान और उपहार केवल प्रतीक हैं, असली मूल्य उस स्नेह और विश्वास का है जो कार्यकर्ताओं और जनता ने उन्हें दिया है।

यह पूरा आयोजन सूरत में केवल एक राजनीतिक कार्यक्रम के रूप में नहीं, बल्कि एक नैतिक और प्रशासनिक संदेश के रूप में देखा गया। इसमें सत्ता के साथ विनम्रता, नेतृत्व के साथ जवाबदेही और सफलता के साथ संवेदनशीलता का संदेश निहित था। राजनीतिक हलकों में इस कार्यक्रम को इस बात का संकेत माना जा रहा है कि आने वाले समय में जनप्रतिनिधियों से केवल विकास कार्य ही नहीं, बल्कि व्यवहारिक अनुशासन और जनता के प्रति संवेदनशीलता की भी अपेक्षा और बढ़ेगी।

इस प्रकार सूरत का यह कार्यक्रम केवल सम्मान समारोह नहीं, बल्कि एक ऐसा मंच बन गया जहाँ राजनीति को सेवा के मूल भाव से जोड़ने की कोशिश स्पष्ट रूप से दिखाई दी।

सूरत में ई-वेस्ट से पर्यावरण संरक्षण की मिसाल: 350 किलो कचरा जुटाकर समाज ने दिखाई हरित जिम्मेदारी

सूरत शहर में पर्यावरण संरक्षण को लेकर एक महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक पहल देखने को मिली, जब लायंस क्लब ऑफ सूरत क्रिस्टल द्वारा आयोजित ई-वेस्ट डोनेशन ड्राइव में लगभग 350 किलो इलेक्ट्रॉनिक कचरा एकत्र किया गया। यह अभियान केवल एक संग्रह कार्यक्रम नहीं था, बल्कि लोगों के बीच पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी और जागरूकता फैलाने का एक संगठित प्रयास था, जिसने यह संदेश दिया कि आधुनिक जीवनशैली के साथ उत्पन्न होने वाले कचरे का सही प्रबंधन उतना ही जरूरी है जितना उसका उत्पादन।

आज के डिजिटल युग में मोबाइल फोन, चार्जर, वायर, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और अन्य गैजेट्स तेजी से बदलते हैं, जिससे ई-वेस्ट की मात्रा लगातार बढ़ रही है। यह कचरा सामान्य कचरे से कहीं अधिक खतरनाक होता है क्योंकि इसमें मौजूद रसायन और धातुएं पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य दोनों के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकते हैं। ऐसे में इस प्रकार के अभियान न केवल कचरे को सही दिशा में निपटाने का माध्यम बनते हैं, बल्कि समाज में एक नई सोच भी विकसित करते हैं।

इस ड्राइव में शहर के लोगों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया और अपने घरों में वर्षों से पड़े पुराने इलेक्ट्रॉनिक सामान को आगे आकर जमा किया। पुराने मोबाइल फोन, खराब चार्जर, इलेक्ट्रॉनिक तार, बैटरी और अन्य अनुपयोगी उपकरण बड़ी मात्रा में एकत्र किए गए। इन सभी को सुरक्षित रूप से रिसाइक्लिंग के लिए एक अधिकृत एजेंसी Reboot को सौंप दिया गया, ताकि उनका वैज्ञानिक तरीके से पुनः उपयोग या निपटान किया जा सके और पर्यावरण पर कोई दुष्प्रभाव न पड़े।

कार्यक्रम के दौरान मौजूद डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लायन मोना देसाई, ज़ोन चेयरपर्सन लायन निशा तातेर, डीसी ई-वेस्ट नरेश प्रजापति और प्रमुख सदस्य लायन भूमि जैन ने इस पहल की सराहना की। उन्होंने कहा कि ई-वेस्ट प्रबंधन आज की सबसे बड़ी जरूरतों में से एक है और यदि समाज इसी तरह जागरूक होता रहा तो आने वाले वर्षों में प्रदूषण के स्तर को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है।

इस अभियान की सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि इसे केवल एक दिन की गतिविधि तक सीमित नहीं रखा गया, बल्कि इसके साथ पर्यावरण सेवा सप्ताह भी मनाया गया, जिसमें लगातार नौ दिनों तक अलग-अलग गतिविधियों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया। इस श्रृंखला में ई-वेस्ट संग्रह से लेकर पौधारोपण, जागरूकता अभियान और स्वच्छता गतिविधियों तक कई कार्यक्रम शामिल रहे।

पहले दिन ई-वेस्ट संग्रह अभियान चलाया गया, जिसमें लोगों ने अपने घरों से अनुपयोगी इलेक्ट्रॉनिक सामान लाकर योगदान दिया। दूसरे दिन पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को बताया गया कि ई-वेस्ट किस तरह मिट्टी, पानी और हवा को प्रभावित करता है। तीसरे दिन किसानों को रासायनिक उर्वरकों के विकल्प के रूप में जैविक खाद वितरित की गई, जिससे कृषि में टिकाऊ और प्राकृतिक पद्धतियों को बढ़ावा दिया जा सके।

चौथे दिन आयोजित ‘सेव अर्थ’ पोस्टर प्रतियोगिता में बच्चों और युवाओं ने अपनी रचनात्मकता के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। पांचवें दिन नीम के पौधे लगाए गए, जो प्राकृतिक औषधीय गुणों के लिए जाने जाते हैं और पर्यावरण संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। छठे दिन बीज वितरण कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को घरों और आसपास हरियाली बढ़ाने के लिए प्रेरित किया गया।

सातवें दिन तापी नदी की सफाई अभियान चलाया गया, जिसमें स्वयंसेवकों ने नदी तट पर जमा कचरे को हटाकर स्वच्छता का संदेश दिया। यह गतिविधि विशेष रूप से महत्वपूर्ण रही क्योंकि नदी प्रदूषण शहरी पर्यावरण के लिए एक गंभीर चुनौती बनता जा रहा है। आठवें दिन पौधों का वितरण किया गया ताकि अधिक से अधिक लोग वृक्षारोपण को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना सकें। नौवें और अंतिम दिन प्लास्टिक के स्थान पर कागज़ के लिफाफों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता अभियान चलाया गया, जिससे सिंगल-यूज़ प्लास्टिक पर निर्भरता कम हो सके।

पूरे अभियान का उद्देश्य केवल कचरा एकत्र करना नहीं था, बल्कि लोगों की सोच में बदलाव लाना था। आयोजकों ने स्पष्ट किया कि यदि ई-वेस्ट को सही तरीके से रिसाइक्लिंग के लिए नहीं भेजा जाता, तो यह धीरे-धीरे पर्यावरण में जहरीले तत्व छोड़कर गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए इसे अलग-अलग संगठनों और अधिकृत रिसाइक्लिंग इकाइयों तक पहुंचाना आवश्यक है।

लायंस क्लब ऑफ सूरत क्रिस्टल की यह पहल इस बात का उदाहरण है कि सामाजिक संगठन यदि लगातार प्रयास करें तो बड़े स्तर पर पर्यावरण संरक्षण संभव है। शहरवासियों की भागीदारी ने यह साबित किया कि जागरूकता और सहयोग के माध्यम से किसी भी अभियान को सफल बनाया जा सकता है।

वारंगल से शुरू हुई भारत की टेक्सटाइल क्रांति, पीएम मित्रा पार्क से लाखों रोजगार और वैश्विक कारोबार को मिलेगी नई रफ्तार

नई दिल्ली। भारत के कपड़ा उद्योग को वैश्विक स्तर पर नई पहचान दिलाने और टेक्सटाइल सेक्टर को आधुनिक औद्योगिक ढांचे से जोड़ने की दिशा में देश ने एक बड़ा कदम आगे बढ़ाया है। प्रधानमंत्री Narendra Modi ने रविवार को तेलंगाना के वारंगल में देश के पहले पीएम मित्रा पार्क का उद्घाटन किया। करीब 1,695.54 करोड़ रुपये की लागत से विकसित यह विशाल परियोजना भारत के टेक्सटाइल सेक्टर के लिए गेम चेंजर मानी जा रही है। केंद्र सरकार का दावा है कि यह परियोजना न केवल कपड़ा उद्योग को नई गति देगी बल्कि बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन, निर्यात वृद्धि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

Warangal में विकसित यह पीएम मित्रा पार्क 1,327 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है और इसे एक आधुनिक, एकीकृत तथा विश्वस्तरीय टेक्सटाइल हब के रूप में तैयार किया गया है। कपड़ा मंत्रालय के अनुसार इस परियोजना में 6,000 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश की संभावना है और इसकी लगभग 62 प्रतिशत भूमि पहले ही विभिन्न उद्योगों और कंपनियों को आवंटित की जा चुकी है। इससे यह संकेत मिलता है कि उद्योग जगत में इस परियोजना को लेकर काफी उत्साह है और आने वाले समय में यहां बड़े स्तर पर औद्योगिक गतिविधियां शुरू हो सकती हैं।

प्रधानमंत्री मोदी ने उद्घाटन समारोह के दौरान कहा कि वारंगल का पीएम मित्रा पार्क देश में टेक्सटाइल क्रांति को नई दिशा देगा। उन्होंने कहा कि भारत लंबे समय से वस्त्र निर्माण की समृद्ध परंपरा वाला देश रहा है और अब आधुनिक तकनीक, एकीकृत औद्योगिक ढांचे और बेहतर लॉजिस्टिक सुविधाओं के माध्यम से देश को वैश्विक टेक्सटाइल हब बनाने की दिशा में तेजी से काम किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने विशेष रूप से महिलाओं के रोजगार का उल्लेख करते हुए कहा कि यह परियोजना हजारों महिलाओं के लिए रोजगार और आत्मनिर्भरता के नए अवसर पैदा करेगी।

कपड़ा मंत्रालय के अनुसार इस पार्क से सीधे तौर पर 24,400 से अधिक रोजगार सृजित होने की उम्मीद है, जबकि अप्रत्यक्ष रूप से हजारों अन्य लोगों को भी रोजगार मिलेगा। परियोजना के निर्माण और प्रारंभिक गतिविधियों के दौरान भी बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों को काम मिला है। सरकार का मानना है कि इस प्रकार की परियोजनाएं केवल औद्योगिक विकास तक सीमित नहीं रहतीं, बल्कि आसपास के क्षेत्रों की आर्थिक गतिविधियों को भी तेज करती हैं।

पीएम मित्रा योजना केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में शामिल है। इसके तहत देश के सात राज्यों — तेलंगाना, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश — में एक-एक मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जा रहे हैं। इन पार्कों को आधुनिक औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में विकसित किया जा रहा है, जहां कपड़ा उद्योग की पूरी मूल्य श्रृंखला एक ही परिसर में उपलब्ध होगी।

अहमदाबाद मण्डल के रेल के कर्मचारियों ने पेश की ईमानदारी की मिसाल, यात्री की खोई हुई सोने की अंगूठी खोजकर लौटाई

पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मण्डल के रेल के कर्मचारियों ने एक बार फिर अपनी ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा से मानवता का परिचय दिया है। इसी क्रम में गाड़ी संख्या 09037 बांद्रा टर्मिनस-भुज स्पेशल के कोच संख्या B8 में यात्रा कर रहे एक यात्री की सोने की अंगूठी अचानक टॉयलेट के ड्रेनेज में गिर गई, जिससे यात्री अत्यंत चिंतित और परेशान हो गए थे। जैसे ही ट्रेन अहमदाबाद स्टेशन पहुँची। श्री संजय यादव, सीनियर सेक्शन इंजीनियर (C&W) और अन्य सुपरवाइजरों और CTS (क्लीन ट्रेन स्टेशन) स्टाफ श्री वीरेंद्र कुमार सिंह ने तुरंत जिम्मेदारी संभाली।

पाइपलाइन और गंदगी के बीच से छोटी सी अंगूठी को ढूंढना एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन रेलवे की इस टीम ने हार नहीं मानी। काफी मेहनत, धैर्य और अथक प्रयास के बाद, टीम ने सफलतापूर्वक उस सोने की अंगूठी को खोज निकाला। यह कार्य केवल अपनी ड्यूटी निभाने तक सीमित नहीं था, बल्कि यह रेल कर्मचारियों की संवेदनशीलता और यात्री के विश्वास के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का उत्कृष्ट उदाहरण है।

श्री संजय यादव और श्री वीरेंद्र कुमार सिंह की इस ईमानदारी और तत्परता ने न केवल एक यात्री की कीमती अमानत को सुरक्षित वापस लौटाया, बल्कि समाज में भारतीय रेल की छवि को भी और अधिक गौरवान्वित किया है।

मजबूत मांग के दम पर गोदरेज प्रॉपर्टीज का बड़ा दांव, 39 हजार करोड़ रुपये की बिक्री का रखा लक्ष्य

नई दिल्ली। देश के रियल एस्टेट सेक्टर में लगातार बढ़ती मांग और ब्रांडेड डेवलपर्स पर ग्राहकों के बढ़ते भरोसे के बीच गोदरेज प्रॉपर्टीज ने चालू वित्त वर्ष 2026-27 के लिए आक्रामक विस्तार रणनीति अपनाई है। कंपनी ने इस वित्त वर्ष में अपनी बिक्री बुकिंग को करीब 14 प्रतिशत बढ़ाकर 39,000 करोड़ रुपये तक पहुंचाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किया है। कंपनी प्रबंधन का मानना है कि आवासीय बाजार में बनी मजबूत मांग और संगठित डेवलपर्स की ओर ग्राहकों का बढ़ता रुझान आने वाले समय में भी कंपनी की वृद्धि को गति देता रहेगा।

कंपनी के कार्यकारी चेयरमैन पिरोजशा गोदरेज ने कहा कि वैश्विक स्तर पर भले ही कई तरह की आर्थिक और भू-राजनीतिक अनिश्चितताएं बनी हुई हों, लेकिन भारतीय आवासीय बाजार की बुनियादी स्थिति मजबूत बनी हुई है। उन्होंने संकेत दिया कि पश्चिम एशिया में जारी तनाव और वैश्विक बाजारों में उतार-चढ़ाव पर कंपनी लगातार नजर बनाए हुए है, लेकिन फिलहाल उसे अपने विकास लक्ष्यों को हासिल करने में किसी बड़ी चुनौती की आशंका नहीं दिख रही।

उन्होंने कहा कि भारतीय रियल एस्टेट बाजार में पिछले कुछ वर्षों में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। ग्राहक अब छोटे और असंगठित डेवलपर्स की तुलना में भरोसेमंद, पारदर्शी और समय पर परियोजनाएं पूरी करने वाले बड़े ब्रांडेड डेवलपर्स को प्राथमिकता दे रहे हैं। इसका सीधा लाभ गोदरेज प्रॉपर्टीज जैसी कंपनियों को मिल रहा है, जिन्होंने गुणवत्ता, विश्वसनीयता और समयबद्ध डिलीवरी के आधार पर बाजार में मजबूत पहचान बनाई है।

Godrej Properties ने पिछले वित्त वर्ष 2025-26 में रिकॉर्ड 34,171 करोड़ रुपये की बिक्री बुकिंग दर्ज की थी। यह कंपनी के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा रहा। खास बात यह है कि कुछ वर्षों पहले यानी वित्त वर्ष 2020-21 में कंपनी की बिक्री बुकिंग केवल 6,725 करोड़ रुपये थी। इस तरह पांच वर्षों के भीतर कंपनी ने अपने कारोबार में कई गुना वृद्धि दर्ज की है। बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि भारत में तेजी से बढ़ते शहरीकरण, मध्यम वर्ग की आय में वृद्धि और घर खरीदने की बढ़ती मानसिकता ने संगठित रियल एस्टेट कंपनियों को मजबूत आधार प्रदान किया है।

पिरोजशा गोदरेज ने बताया कि मार्च महीने में पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और वैश्विक अनिश्चितताओं का असर कुछ समय के लिए ग्राहकों की खरीदारी गतिविधियों पर दिखाई दिया था। हालांकि अप्रैल से स्थिति में सुधार आया और बिक्री की गति फिर सामान्य हो गई। उन्होंने कहा कि कंपनी को आने वाले महीनों में आवासीय मांग में और मजबूती की उम्मीद है।

कंपनी ने चालू वित्त वर्ष में ग्राहकों से 24,000 करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य भी तय किया है। पिछले वित्त वर्ष में कंपनी ने ग्राहकों से 19,965 करोड़ रुपये का संग्रह किया था। यह बढ़ोतरी बताती है कि कंपनी केवल नई बिक्री पर ही नहीं बल्कि नकदी प्रवाह को मजबूत रखने पर भी फोकस कर रही है। मजबूत कैश फ्लो किसी भी रियल एस्टेट कंपनी के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इससे परियोजनाओं को समय पर पूरा करने और विस्तार योजनाओं को गति देने में मदद मिलती है।

गोदरेज प्रॉपर्टीज ने नए भूखंडों और परियोजनाओं के अधिग्रहण की रणनीति पर भी आक्रामक रुख बनाए रखा है। कंपनी का कहना है कि वह ऐसी परियोजनाओं को अपने पोर्टफोलियो में जोड़ना चाहती है जिनसे लगभग 20,000 करोड़ रुपये का संभावित राजस्व हासिल किया जा सके। पिछले वित्त वर्ष 2025-26 में कंपनी ने 18 नए भूखंडों का अधिग्रहण किया था, जिनकी अनुमानित राजस्व क्षमता करीब 42,100 करोड़ रुपये आंकी गई है। इससे स्पष्ट है कि कंपनी केवल मौजूदा परियोजनाओं तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि भविष्य की मांग को देखते हुए अपने भूमि बैंक और प्रोजेक्ट पाइपलाइन को लगातार मजबूत कर रही है।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल अहमदाबाद के सनातन रामधाम मंदिर में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में सहभागी हुए

मुख्यमंत्री ने नवनिर्मित श्री राम दरबार तथा अन्य मूर्तियों के दर्शन कर राज्य के नागरिकों की सुख-समृद्धि के लिए मंगलकामनाएँ कीं

गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल रविवार को अहमदाबाद में थलतेज स्थित श्री सनातन रामधाम मंदिर में आयोजित मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में उपस्थित रहे।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल श्री राम दरबार तथा अन्य मूर्तियों के दर्शन-पूजन कर महाआरती में सहभागी हुए और उन्होंने राज्य के नागरिकों की सुख-समृद्धि के लिए मंगलकामनाएँ कीं। महोत्सव में पूर्व उप मुख्यमंत्री श्री नीतिनभाई पटेल भी उपस्थित रहे।

लगभग 90 वर्ष पुराने इस मंदिर का गुजरात पवित्र यात्राधाम विकास बोर्ड तथा अन्य दाताओं के सहयोग से जीर्णोद्धार किया गया है।

मुख्यमंत्री ने इस मंदिर के मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के 10 दिवसीय महोत्सव के अंतिम दिन रविवार को उपस्थित रहकर भक्ति एवं सनातन संस्कारों के अविरत केंद्र समान रामधाम मंदिर में दर्शन कर धन्यता की अनुभूति की।

श्री भूपेंद्र पटेल मंदिर के गर्भगृह में शास्त्रोक्त विधि-विधान तथा मंत्रोच्चार के साथ आयोजित पूजा विधि में सहभागी हुए। इस अवसर पर ‘जय श्री राम’ तथा ‘श्री रामधुन’ से समग्र वातावरण भक्तिमय बन गया।